





## फर्नीचर घोटाला मामले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई

**अंबिकापुर।** राजीव गांधी शिक्षा मिशन में वर्ष 2011-12 के दौरान सामने आए करोड़ों रुपये के कथित फर्नीचर घोटाले के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (इच्छ) ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में,इच्छ ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी एसपी पाण्डेय और दर्शन फेब्रिकेशन फर्म के प्रोपराइटर संजय पटेल समेत तीन लोग शामिल हैं। ऑनलाइनकोर्स और शिक्षा विकल्प तलाशना बताया जा रहा है कि वर्ष 2011-12 में राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत फर्नीचर खरीदी में बड़े पैमाने पर अनियमितता और वित्तीय गड़बड़ी सामने आई थी।

जांच के दौरान सामने आए दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर एसीबी ने यह कार्रवाई की है।मामले की जांच के सिलसिले में करीब दो माह

### 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार



पहले एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने संबंधित कार्यालय पहुंचकर फर्नीचर खरीदी से जुड़े दस्तावेजों की जांच की थी। इस दौरान टीम ने फर्नीचर खरीदी से संबंधित हार्ड दस्तावेजों के साथ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स भी जब्त किए थे।

जब्त दस्तावेजों और जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर अब एसीबी ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वर्ष 2011-12 में हुए इस कथित फर्नीचर घोटाले की जांच में विभाग के 6 से 7 अधिकारियों के नाम सामने आए थे। इसके अलावा फर्नीचर

स्प्लाई और खरीदी से जुड़े करीब 12 फर्मों की भूमिका भी जांच के दायरे में रही है। मामले में एसीबी ने आईपीसी की धारा 420 और 120(B) के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम(पीसी एक्ट) की धारा 13(1) और 13(2) के तहत अपराध दर्ज किया था।फिलहाल तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। एसीबी द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर घोटाले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका को लेकर भी जांच जारी है।

## गंगरेल बांध लबालब, 87 प्रतिशत से अधिक भरा पानी

**धमतरी।** छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलाशयों में शामिल रविशंकर सागर यानी गंगरेल बांध लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से लबालब हो गया है। बांध में 87 फीसदी से ज्यादा पानी भर चुका है और कैचमेंट एरिया में अभी भी झमाझम बारिश जारी है। गंगरेल कोई छोटा तालाब नहीं है, ये जो जलाशय है, जिससे सैकड़ों गांवों की किस्मत जुड़ी है और अब यही गंगरेल बाढ़ का खतरा बन गया है। दरअसल, गंगरेल के साथ-साथ मुरमसिल्ली, दुधावा और सोंदूर बांध में भी जबरदस्त जलभराव हो गया है। प्रशासन के अनुसार, गंगरेल में लगातार पानी की आवक जारी है। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सैलानियों और निचले इलाकों के ग्रामीणों को नदी किनारे न जाने की सख्त हिदायत दी गई है। जिला कलेक्टर की मानें तो अगर बारिश इसी तरह जारी रही तो गंगरेल के गेट किसी भी वक खोले जा सकते हैं। आपको बता दें, गंगरेल में 55 हजार क्यूसेक पानी छोड़ने पर ही 72 गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है और पिछली बार जब गेट खुले थे तो 1.31 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद तो हालात और बिगड़ गए थे। फिलहाल महानदी में पानी की आवक 12.97 टीएमसी हो रही है और सामान्य बहाव है, लेकिन ओडिशा सीमा तक के गांवों में दहशत का माहौल है। सबकी जुबान पर एक ही तस्वाल है, क्या फिर लौटेंगा 2024 जैसी बाढ़ का मंजर ?



## बिलासपुर स्टेशन में दपूमरे का पहला वॉशिंग सेंटर इकोग्रीन ऑटो केयर

**बिलासपुर।** दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर मंडल द्वारा यात्रियों एवं वाहन मालिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक और अभिनव पहल की गई है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन का पार्किंग परिसर में इकोग्रीन ऑटो केयर नाम से आधुनिक वॉशिंग सेंटर की सुविधा प्रारंभ की गई है। इस पहल का उद्देश्य रेलवे परिसरों में यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाजनक, आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना है। इकोग्रीन ऑटो केयर के माध्यम से रेलवे स्टेशन आने-जाने वाले यात्रियों के साथ स्थानीय वाहन मालिक भी लाभान्वित होंगे।

यह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में प्रारंभ किया गया पहला वॉशिंग सेंटर है, जहां रेलवे स्टेशन आने वाले यात्रियों के साथ-साथ आम वाहन मालिक भी अपने वाहनों की वॉशिंग एवं क्लीनिंग की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। यहां कार, बाइक, स्कूटी, ऑटो सहित विभिन्न प्रकार के वाहनों की वॉशिंग बाजार की तुलना में किफायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। रेलवे स्टेशन के कार पार्किंग परिसर में वॉशिंग सेंटर की सुविधा उपलब्ध होने से यात्रियों को अपने वाहन की सफाई के साथ ही वाहन की पाफ़-सफाई एवं वॉशिंग की सुविधा भी एक ही स्थान पर मिल



सकेगी। इससे यात्रियों एवं वाहन मालिकों के समय और श्रम की बचत होगी तथा उन्हें शहर में अलगा से वॉशिंग सेंटर तलाशने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही गाडियों के पंचर, मामूली रिपेयरिंग, छोटे-छोटे स्पेयर पार्ट जैसे सीट कवर, हेल्मेट इत्यादि की सुविधा भी प्राप्त होगी।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अनुराग कुमार सिंह ने बताया – बिलासपुर स्टेशन पर इकोग्रीन ऑटो केयर वॉशिंग सेंटर की शुरुआत यात्रियों एवं वाहन

## कोरबा बांगो बांध से छोड़े गए पानी का बड़ा असर

**कोरबा।** मिनीमाता हसदेव बांगो बांध के नौ गेट पिछले 60 घंटे से लगातार खुले हुए हैं। 93.65 प्रतिशत जलभराव के बाद बांध में पानी का दबाव नियंत्रित करने के लिए 11 में नौ गेट खोले गए हैं। इनसे 48,828 क्यूसेक पानी प्रति सेकेंड की दर से हसदेव नदी में छोड़ा जा रहा है। लगातार पानी छोड़े जाने से हसदेव का जलप्रवाह तेज बना हुआ है और नदी किनारे के निचले क्षेत्रों में प्रशासन की निगरानी बढ़ा दी गई है।बांगो में इस बार मानसून की वर्षा ने जलभराव की स्थिति जल्दी बना दी। लंबे अंतराल बाद बांध के नौ गेट एक साथ खुले हैं। इससे पहले वर्ष 2014 के पूर्व बांध लबालब होने की स्थिति में 10 गेट खोलने पड़े थे। उस समय भी अतिरिक्त पानी



को बाहर निकालने के लिए बड़े स्तर पर पानी छोड़ा गया था। वर्तमान में बांगो के दो, तीन, चार, आठ, नौ और 10 नंबर गेट एक-एक मीटर, पांच और सात नंबर गेट डेढ़ मीटर तथा छह नंबर गेट दो मीटर खोला गया है। लगातार पानी छोड़ने से बांध के जलस्तर में करीब आठ सेंटीमीटर की कमी आई है।

## नीचे अस्पताल ऊपर स्कूल, जर्जर भवन के चलते अस्पताल में पढ़ने को मजबूर मासूम

**मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर।** मनेंद्रगढ़ में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली की तस्वीर सामने आई है. यहां जर्जर स्कूल भवन में पानी और करंट के खतरे की वजह से 41 बच्चों को स्कूल से हटाकर उप स्वास्थ्य केंद्र के दो कमरों में पढ़ाया जा रहा है। मनेंद्रगढ़ के वार्ड क्रमांक 8 में शासकीय प्राथमिक विद्यालय है। इस स्कूल का भवन लंबे समय से जर्जर है। बारिश शुरू होते ही स्कूल की छत से पानी टपकने लगा। भवन के अंदर पानी भर गया। पानी भरने के कारण बिजली के करंट का खतरा भी पैदा हो गया। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल की बिजली सप्लाई बंद कर भवन में ताला लगा दिया गया है। अब इस स्कूल को बगल में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र के खाली भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। अब सिर्फ दो छोटे कमरों में 41 बच्चों की कक्षाएं चल रहीं हैं। कम जगह के कारण बच्चों को बैठने और पढ़ाई करने में परेशानी हो रही है। बिजली और पंखे की व्यवस्था नहीं होने से बारिश और उमस के बीच बच्चों और शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व पार्षद अजमुद्दीन अंसारी ने बताया कि स्कूल भवन में बारिश का पानी भरने के साथ बिजली करंट की समस्या भी बनी हुई थी। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें उप स्वास्थ्य केंद्र के दो कमरों में शिफ्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि



वहां भी बारिश का पानी आने की शिकायत है। जिला शिक्षा अधिकारी रविकांत यादव ने बताया कि स्कूल भवन की जांच कराई गई थी। भवन की मरम्मत के लिए पिछले साल राशि आई थी, लेकिन इंजीनियर की जांच में सामने आया कि भवन बिना कॉलम के बना है। इसकी मरम्मत के लिए स्वीकृत राशि से ज्यादा राशि की आवश्यकता होगी, जिसके कारण राशि वापस हो गई। बारिश के दौरान स्कूल की छत से पानी टपक रहा था। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें स्कूल के बगल में स्थित खाली चिकित्सा भवन में शिफ्ट किया गया है। स्कूल भवन की मरम्मत का प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है। प्रधान पाठक को आकस्मिक निधि से तत्काल बिजली और पंखे की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

### एसईसीएल में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत शपथ कार्यक्रम आयोजित

**बिलासपुर।** भारत सरकार की

पहल नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) मुख्यालय में नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता एवं जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एसईसीएल के सीएमडी हरीश दुहन ने प्रशासनिक भवन में निदेशक (तकनीकी/संचालन) एन. फैंकलिन जयकुमार, निदेशक (मानव संसाधन) बिरंची दास, मुख्य सतर्कता अधिकारी हिमांशु जैन सहित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नशे के विरुद्ध जागरूकता फैलाने तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय सहभागिता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने नशा छोड़ें, जीवन जोड़ें के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने तथा नशा मुक्त भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। एसईसीएल द्वारा नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ एवं नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए जनभागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है।



### अग्रवाल महिला मंडल ने हर्षोल्लास से मनाया तीज उत्सव

**राजनांदगांव।** अग्रवाल महिला मंडल राजनांदगांव द्वारा सावन के पावन अवसर पर तीज उत्सव एवं सिंधारा उत्सव का आयोजन अग्रसेन भवन में बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम में समाज की महिलाओं एवं युवतियों ने बढ़-चढ़कर सहभागिता निभाई। पारंपरिक वेशभूषा, नृत्य, मनोरंजक खेलों और विभिन्न प्रतियोगिताओं ने पूरे आयोजन को उत्सवमय बना दिया। कार्यक्रम के दौरान नई विवाहित एवं नवयुवतियों का सिंधारा उत्सव मनाया गया।



रीति-रिवाजों के साथ सावन और तीज की खुशियां साझा कीं। आयोजन में महिलाओं एवं युवतियों ने आकर्षक नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। उत्सव में प्रसन्नोत्तरी राउंड का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इसके अलावा हाऊजी गेम का आयोजन भी किया गया, जिसका महिलाओं ने जमकर आनंद लिया। पूरे कार्यक्रम में हंसी-खुशी और उत्साह का माहौल बना रहा। कार्यक्रम के दौरान मास्टर अवयन को राज्य स्तरीय कैप्ट प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल प्राप्त करने पर अग्रवाल महिला मंडल द्वारा सम्मानित किया गया।

### एसईसीएल में नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम आयोजित

**बिलासपुर।** भारत सरकार की पहल नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) मुख्यालय में नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता एवं जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एसईसीएल के सीएमडी हरीश दुहन ने प्रशासनिक भवन में निदेशक (तकनीकी/संचालन) एन. फैंकलिन जयकुमार, निदेशक (मानव संसाधन) बिरंची दास, मुख्य सतर्कता अधिकारी हिमांशु जैन सहित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नशे के विरुद्ध जागरूकता फैलाने तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय सहभागिता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने नशा छोड़ें, जीवन जोड़ें के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने तथा नशा मुक्त भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। एसईसीएल द्वारा नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ एवं नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए जनभागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

### ‘कीटनाशक विक्रय केंद्रों का किया गया औचक निरीक्षण

**बलौदाबाजार।** कलेक्टर के निर्देशानुसार कृषि विभाग द्वारा खरीफ अंतर्गत वर्तमान कृषि कार्य को दृष्टिगत रखते हुए कृषकों की गुणवत्तायुक्त कीटनाशक दवाई उपलब्ध कराने के उद्देश्य जिले के कीटनाशक निरीक्षकों द्वारा नियमित रूप से कीटनाशक विक्रय केंद्रों में दबिश देकर सघन निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर 3 विक्रेताओं को नोटिस जारी किया। विखे पलारी के निरीक्षक सुचिन कुमार वर्मा ने ग्राम संडी में संचालित महेंद्र कृषि सेवा केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विक्रय केंद्र में कैश मेमो तथा स्रोत प्रमाण पत्र का उचित संधारण नहीं पाए जाने के कारण विक्रेता को कारण बताओं नोटिस जारी किया है। ग्राम संडी के ही भगत कृषि सेवा केंद्र के निरीक्षण के दौरान स्रोत प्रमाण पत्र का उचित संधारण नहीं पाए जाने के कारण विक्रेता को कारण बताओं नोटिस जारी किया है। आवास निर्माण के दौरान फूलमत बाई को मनरेगा के तहत 90 दिवस की अनुशुल श्रम मजदूरी का लाभ भी मिला। इससे उन्हें अतिरिक्त आर्थिक संबल मिला।

### पीएम आवास ने फूलमत बाई को दिया पक्की छत का सहारा

**कोरिया।** 70 वर्षीय श्रीमती फूलमत बाई के जीवन में अब खुशियों ने दस्तक दी है। पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत मिले पक्के आवास ने उन्हें सुरक्षित छत के साथ सम्मानजनक जीवन का भरोसा दिया है। शासन की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़कर उनका एकाकी और कठिन जीवन अब पहले से कहीं आसान हो गया है। पति के निधन के बाद फूलमत बाई के सामने सुरक्षित आवास और आर्थिक जरूरतों की चुनौती थी। वे अपनी बेटी और दामाद के साथ जर्जर मिट्टी के मकान में जीवनयापन कर रही थीं। पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृत होने के बाद पहली किश्त मिलते ही निर्माण शुरू हुआ और आज उनके पास अपना मजबूत पक्का मकान है। पक्की छत ने उन्हें मौसम की परेशानियों से राहत देने के साथ जीवन में सुरक्षा और आत्मसम्मान भी दिया है। आवास निर्माण के दौरान फूलमत बाई को मनरेगा के तहत 90 दिवस की अनुशुल श्रम मजदूरी का लाभ भी मिला। इससे उन्हें अतिरिक्त आर्थिक संबल मिला।

### ग्राम छिलपावन में अफीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि

**महासमुंद ।** जिले के विकासखंड महासमुंद अंतर्गत ग्राम छिलपावन में सूकर पालक के यहां लिए गए सैपल की जांच के बाद अफ्रीकन स्वाइन फीवर की धनात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। संक्रमण की पुष्टि के बाद पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग द्वारा निर्धारित प्रावधानों के तहत ग्राम छिलपावन के 1 किलोमीटर की परिधि को इन्फेक्टेड जोन तथा 1 से 10 किलोमीटर की परिधि को सर्विलेंस जोन घोषित किया गया है। यह व्यवस्था आगामी आदेश तक अथवा अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगी। यह कार्रवाई संचालनालय पशु चिकित्सा सेवाएं, रायपुर द्वारा जारी निर्धारित प्रावधानों के तहत की गई है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन्फेक्टेड जोन से सूकर एवं सूकर उत्पादों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही सर्विलेंस जोन में सूकरों से संबंधित बाजार एवं दुकानें पूर्णतः बंद रखी जाएंगी। संबंधित विभागों एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा क्षेत्र में निगरानी और आवश्यक निबंधनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

### राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिशन से किसानों को मिल रहा लाभ

**अम्बिकापुर।** राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिशन अंतर्गत मोटा अनाज योजना के माध्यम से जिले के किसानों को फसल उत्पादन के लिए आवश्यक सहयोग, गुणवत्तापूर्ण बीज एवं तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के तहत किसानों को कृषि की वैज्ञानिक पद्धतियों से जोड़ते हुए बेहतर उत्पादन और आय में वृद्धि के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम कृष्णापुर किसान रमेश ने इस वर्ष कृषि विभाग के मार्गदर्शन में 2 एकड़ क्षेत्र में मक्का की खेती की है। ग्राम सेवक के माध्यम से उन्हें 2 एकड़ के लिए मक्का का बीज नि:शुल्क उपलब्ध कराया। वर्तमान में उनकी मक्का की फसल अच्छी स्थिति में है और खेत में फसल की बढ़वार देखकर वे उत्साहित हैं। रमेश रजवाड़े बताते हैं कि पिछले वर्ष वे उड़द की खेती कर रहे थे, लेकिन इस वर्ष शासन के मार्गदर्शन पर उन्होंने मक्का की खेती करने का निर्णय लिया। कृषि विभाग द्वारा उन्हें मक्का बीज उपलब्ध कराने के साथ ही फसल को कतार में लगाने की जानकारी दी गई।

# पसंदीदा जगह ट्रान्सफर मांगने को हाईकोर्ट ने माना अनुचित

**बिलासपुर।** छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्थानांतरण से जुड़े एक महत्वपूर्ण एकर निर्णय में स्पष्ट किया है कि कर्मचारी किसी विशेष स्थान पर पदस्थापना को अपना अधिकार नहीं मान सकता। प्रशासनिक आवश्यकता और विभागीय व्यवस्था के अनुरूप कर्मचारी का स्थानांतरण करना सक्षम प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में है।

जस्टिस बिभु दत्ता गुरु ने यह टिप्पणी उस मामले में की, जिसमें एक कर्मचारी ने अपने मूल पदस्थापना स्थल नगर पालिक निगम रायपुर में वापस भेजे जाने की मांग करते हुए बाद में किए गए स्थानांतरण को चुनौती दी थी। मामले के अनुसार कर्मचारी की प्रारंभिक नियुक्ति नगर पालिक निगम रायपुर में हुई थी। इसके बाद उसे रायपुर से नगर पालिक निगम रिसाली और बाद में रिसाली से नगर पालिक निगम भिलाई-चरौदा स्थानांतरित किया गया। कर्मचारी का दावा था कि दोनों स्थानों पर उसे



स्वीकृत पदों की तुलना में अतिरिक्त यानी सरप्लस कर्मचारी माना गया। इसी आधार पर उसने अपने मूल संस्थान रायपुर नगर निगम में प्रत्यावर्तन की मांग की। कर्मचारी ने अपनी मांग को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया।न्यायालय के निर्देश के बाद उसने विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, निर्धारित अवधि में निर्णय नहीं होने पर अवमानना कार्यवाही भी प्रारंभ हुई। कार्यवाही लंबित रहने के दौरान कर्मचारी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी ने उसे रायपुर वापस भेजने

के बजाय भिलाई-चरौदा से नगर पालिक निगम राजनांदगांव ट्रान्सफर कर दिया।कर्मचारी ने इस आदेश को चुनौती देते हुए रायपुर में पदस्थापना की मांग की।उसकी ओर से यह भी तर्क दिया गया कि अधिकारी की स्थिति में उससे सहमति लेकर डिपुटेशन के माध्यम से समायोजित किया जा सकता था। प्रार्थी की दलीलों पर विचार करते हुए जस्टिस बिभु दत्ता गुरु ने कहा कि कर्मचारी का वर्तमान पदस्थापन यदि सरप्लस है और उसे दूसरे निगम में स्थानांतरित किया गया है, तो केवल अपनी विशेष निगम में पोस्टिंग का दावा नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि सरप्लस कर्मचारी को किस स्थान पर समायोजित किया जाए, उसे किसी विशेष स्थान पर स्थानांतरित यह मूलतः प्रशासनिक निर्णय है।न्यायालय सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी के निर्णय के

स्थान पर अपनी पसंद की पोस्टिंग निर्धारित नहीं कर सकता। कोर्ट ने कर्मचारी के इस तर्क को भी स्वीकार नहीं किया कि लगातार स्थानांतरण के कारण वर्तमान आदेश अवैध हो जाता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी कर्मचारी का एक से अधिक बार स्थानांतरण होना, अपने आप में, बाद के स्थानांतरण आदेश को अवैध नहीं बनाता। रायपुर से रिसाली, रिसाली से भिलाई-चरौदा और फिर राजनांदगांव स्थानांतरण होने के बावजूद, केवल लगातार ट्रान्सफर के आधार पर न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने नम्रता वर्मा बनाम राज्य शासन उच्च प्रदेश एवं अन्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कहा कि कर्मचारी यह आग्रह नहीं कर सकता कि उसे किसी विशेष स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। वहां से स्थानांतरित न किया जाए।

## दंतेवाड़ा में दुर्लभ माउस डियर पर कुत्तों का हमला

**दंतेवाड़ा।** बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में बुधवार को एक माउस डियर पर कुत्तों ने हमला कर दिया। उसके बाद माउस डियर भागकर दंतेवाड़ा केलक्ट्रेट परिसर में पहुंच गया। इस बात की सूचना कलेक्ट्रेट परिसर में तैनात कर्मचारियों ने वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और माउस डियर को रेस्क्यू किया गया। वनमंडलाधिकारी के मार्गदर्शन में वन विभाग के कर्मचारियों ने माउस डियर को सुरक्षित कब्जे में लिया। इसके बाद पशु चिकित्सा अधिकारी ने उसकी जांच की। पशु चिकित्सा अधिकारी ने उसका आवश्यक उपचार किया। वनकर्मियों ने उसके स्वास्थ्य एवं व्यवहार पर लगातार निगरानी रखी। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद माउस डियर पूरी तरह स्वस्थ पाया गया। वन विभाग की टीम ने उसे बचेली वन क्षेत्र के उपयुक्त प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया। माउस डियर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-द्व में सूचीबद्ध वन्यजीव है। इसके संरक्षण को विशेष महत्व दिया जाता है। वन विभाग की तत्परता से इस दुर्लभ वन्यजीव को सुरक्षित बचाकर उसके प्राकृतिक



आवास में वापस पहुंचाया गया। वन विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि आबादी क्षेत्र में किसी भी वन्यजीव के दिखाई देने पर उसे पकड़ने, भगाने या उसके पास जाने की कोशिश न करें। वन्यजीव को अनावश्यक रूप से घेरने से वह डरकर खुद को चोट पहुंचा सकता है। वन्यजीव दिखाई देने पर तत्काल निकटतम वन विभाग कार्यालय या वन अमले को सूचना दें, जिससे उसका सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सके।



## संक्षिप्त समाचार

**छत्तीसगढ़ को जल्द मिल सकते हैं****भाजपा प्रभारी : अजय चंद्राकर**

रायपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक अजय चंद्राकर ने अन्य प्रदेशों की तरह छत्तीसगढ़ में भी जल्द ही भाजपा प्रभारी की नियुक्ति की बात कही है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का विशेषाधिकार बताते हुए कहा कि वो जब चाहे तब सोच समझ के कर सकते हैं। लेकिन जो भी आएगा, अच्छा ही होगा। वरिष्ठ भाजपा नेता अजय चंद्राकर ने मीडिया से चर्चा में सरकार के ढाई साल पूरे होने पर मंत्रियों की प्रेसवार्ता पर कांग्रेस के केवल पोस्टर में विकास होने के तंत्र पर पलटवार करते हुए कहा कि अपने समय के विकास को कांग्रेस विकास समझती है, तो भगवान छत्तीसगढ़ को कांग्रेस से बचाए। वो किस विषय में बात करेंगे? कांग्रेस के विकास का मॉडल दूसरा है। जेल तीर्थ स्थल था। लोग वहां जाने में गर्व महसूस करते थे। वहीं शिक्षा व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के बयान पर अजय चंद्राकर ने कहा कि पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था केंद्र से संबंधित विषय है। जो जो समस्याएं हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। पूरे देश के युवा जागृत हैं। वहीं बैज के शिक्षा मंत्री के रील बनाने में व्यस्त रहने वाले बयान पर अजय चंद्राकर ने कहा कि दीपक बैज रील के नेता है। उन्हें सार्वजनिक तौर पर भूपेश बघेल को अपना नेता मानने के लिए परेशानी होती है।

**स्वास्थ्य मंत्री से मिले इंटरनैक्ट, आंदोलन स्थगित करने का लिया निर्णय**

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी



जायसवाल ने प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के इंटरनैक्टों से मुलाकात कर उनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक चर्चा की। इस दौरान इंटरनैक्टों ने स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा के बाद प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार पर विश्वास जताते हुए अपना आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया, जिस पर सभी ने संतोष व्यक्त किया। चर्चा में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आईएमए-एमएसएन छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और संबंधित प्रकरण पर पहल करते हुए इंटरनैक्टों के स्ट्राटेज में वृद्धि से जुड़ी आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बताया गया कि इंटरनैक्टों की मांगों पर इसी माह आवश्यक एवं सकारात्मक निर्णय लेने के लिए विभागीय स्तर पर प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार चिकित्सा शिक्षा से जुड़े सभी विषयों के प्रति संवेदनशील है और इंटरनैक्टों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

**छत्तीसगढ़ डक परिमंडल ने लॉन्च किया**

**राखी स्पेशल गिफ्ट बॉक्स**

रायपुर। रक्षाबंधन के पावन पर्व को और अधिक खास बनाने के लिए भारतीय डाक विभाग के छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल द्वारा एक विशेष पहल की गई है। डाक विभाग इस वर्ष भाई-बहन के अटूट और अनमोल रिश्ते के लिए एक बेहद आकर्षक और प्रीमियम राखी स्पेशल गिफ्ट बॉक्स लेकर आया है। अनमोल तोहफा, अनमोल रिश्ते के लिए के संदेश के साथ तैयार यह बॉक्स उत्सव की खुशियों को दोगुना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आम जनमानस की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह विशेष गिफ्ट बॉक्स मात्र 520/- (पांच सौ बीस रुपये मात्र) की बेहद किफायती कीमत पर नजदीकी डाकघरों में बिज्जी के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए प्रणव कुमार (मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, छत्तीसगढ़ परिमंडल) ने कहा कि छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल ने इस बार एक विशेष राखी स्पेशल गिफ्ट बॉक्स तैयार किया है। मात्र 520 की बेहद किफायती कीमत पर उपलब्ध इस प्रीमियम बॉक्स में दो आकर्षक राखियों के साथ-साथ पारंपरिक अक्षत-कुमकुम, बैज, फ्रिज मैग्नेट, पिक्चर पोस्टकार्ड और की-रिंग जैसी सर्व-सुविधाजनक वस्तुएं दी गई हैं ताकि बहनों को पूजा और उपहार के लिए अलग-अलग न भटकना पड़े।

**रायपुर ग्रामीण पुलिस में 6**

**निरीक्षकों का तबादला**

रायपुर। रायपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक श्वेता श्रीवास्तव ने 6 निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से नई पदस्थापना पर भेजने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कुछ थाना प्रभारियों को बदला गया है, जबकि पुलिस लाइन में पदस्थ निरीक्षकों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जारी आदेश के मुताबिक प्रेम प्रकाश अवधिया पुलिस लाइन, रायपुर ग्रामीण से थाना प्रभारी, थाना-राखी, आशीष सिंह राजपूत थाना प्रभारी, थाना-राखी से पुलिस लाइन, रायपुर ग्रामीण, कृष्ण कुमार कुशवाहा थाना प्रभारी, थाना-खरोरा से पुलिस लाइन, रायपुर ग्रामीण, प्रदीप बिसेन पुलिस लाइन, रायपुर ग्रामीण से चौकी प्रभारी, उपरवारा चौकी, विद्याभूषण भारद्वाज पुलिस लाइन, रायपुर ग्रामीण से थाना प्रभारी, थाना-खरोरा तथा कमलेश कुमार गुप्ता पुलिस लाइन, रायपुर ग्रामीण से चौकी प्रभारी, सिलयारी चौकी में पदस्थ किया गया है।

## फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट मामले की सुनवाई के लिए बनेगा विशेष मेडिकल बोर्ड

**समाज कल्याण मंत्री राजवाड़े व स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने ली संयुक्त बैठक, त्वरित जांच कर दी जाएगी रिपोर्ट**

रायपुर। दिव्यांगजनों, उभयलिंगी समुदाय तथा अन्य अंतर्विभागीय विषयों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से बुधवार को महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर में समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की संयुक्त बैठक आयोजित की गई।

बैठक में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के आधार पर शासकीय सेवा में कार्यरत 186 व्यक्तियों से संबंधित प्रकरणों की जांच सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप राज्य मेडिकल बोर्ड अथवा संभागीय मेडिकल बोर्ड के माध्यम से कराए जाने पर चर्चा हुई। संबंधित व्यक्तियों को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर परीक्षण कराने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने तथा निर्धारित समयान्तराल में दिव्यांगता की भौतिक जांच के लिए उपस्थित होने वाले व्यक्तियों के प्रकरणों की समीक्षा किए जाने पर भी विचार-विमर्श किया गया। अधिकारियों ने बताया कि फर्जी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के आधार पर शासकीय सेवाओं

में कार्यरत व्यक्तियों की जांच के लिए राज्य मेडिकल एवं संभागीय मेडिकल बोर्ड में परीक्षण की प्रक्रिया को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश तय किए जाएंगे।

बैठक में दिव्यांगजनों के दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने, मेडिकल बोर्ड में विषय-विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष मेडिकल बोर्ड एवं दिव्यांगता परीक्षण शिविर आयोजित करने पर चर्चा की गई। पात्र दिव्यांगजनों को समयबद्ध रूप से प्रमाण-पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप अस्थायी एवं स्थायी दिव्यांगता के लिए पृथक ट्रांसजेंडर क्लीनिक/वार्ड की व्यवस्था किए जाने पर भी चर्चा हुई।

बैठक में उभयलिंगी समुदाय के व्यक्तियों के लिए राज्य की सेक्स रिसाइनमेंट सर्जरी



संबंधी सहायता तथा समय-सीमा में पात्र हितग्राहियों को लाभ प्रदान करने पर चर्चा हुई। स्कू से लिए सहायता अनुदान संबंधी दिशा-निर्देशों में आवश्यक सर्जरी को शामिल किए जाने तथा निर्धारित दरों में वर्तमान बाजार दर के अनुरूप संशोधन की कार्यवाही पर विचार किया गया। राज्य के शासकीय अस्पतालों में उभयलिंगी व्यक्तियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पृथक ट्रांसजेंडर क्लीनिक/वार्ड की व्यवस्था किए जाने पर भी चर्चा हुई।

बैठक में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित नशामुक्ति केंद्रों की समीक्षा की गई। मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुरूप राज्य में संचालित नशामुक्ति केंद्रों के पंजीयन तथा

मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण से संबंधित प्रक्रिया की समीक्षा की गई।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा नशामुक्ति केंद्रों में उपचाररत व्यक्तियों को दी जा रही दवाओं के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने तथा केंद्रों के विस्तार एवं बेहतर संचालन पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, भिक्षुक, उभयलिंगी एवं नशा पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं संस्थागत संरक्षण के लिए संचालित शासकीय एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं में निवासरत हितग्राहियों के स्वास्थ्य परीक्षण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी सहमति बनी। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया, समाज कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार, स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त सह संचालक श्री संजीव झा, समाज कल्याण विभाग के संचालक रणवीर शर्मा सहित दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

**सियान गुड़ी एवं वृद्धाश्रमों में बेहतर सुविधाओं और नियमित मॉनिटरिंग पर जोर**

समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी

राजवाड़े ने आज मंत्रालय में समाज कल्याण विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक लेकर विभागीय योजनाओं की प्रगति एवं क्रियान्वयन की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना सुनिश्चित करें।

बैठक में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों के वितरण, सियान गुड़ी एवं वृद्धाश्रमों में उपलब्ध सुविधाओं तथा हितग्राहीमूलक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्री ने सहायक उपकरणों के वितरण में तेजी लाने तथा सियान गुड़ी एवं वृद्धाश्रमों में भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की नियमित निगरानी के निर्देश दिए। श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि सुशासन सरकार समाज के प्रत्येक जरूरतमंद, दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिक को सम्मानपूर्ण जीवन और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ नियमित निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

## खाद्य मंत्री की अध्यक्षता में जीवन दीप

**समिति की साधारण सभा संपन्न**

रायपुर। खाद्य मंत्री एवं सुरजपूर

जिले के प्रभारी मंत्री श्री दयालदास बघेल की अध्यक्षता में आज जीवन दीप समिति की साधारण सभा की बैठक संपन्न हुई। जिला संयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा समिति के आय-व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, जिस पर विस्तार से चर्चा करते हुए जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आमजन को बेहतर और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में जनसमुदाय की आवश्यकता के अनुरूप स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार तथा उपलब्ध कार्यों के अधिकतम एवं बेहतर उपयोग पर चर्चा की गई। इसके साथ ही अस्पताल भवन एवं परिसर में

आवश्यक निर्माण तथा मरम्मत कार्य, मरीजों एवं उनके परिजनों की सुविधा, अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं की सुदृढ़ करने के विषयों पर विचार किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन एवं कार्य अवधि में वृद्धि सहित अन्य आवश्यकताओं पर भी चर्चा हुई। विभिन्न एजेंडों पर विचार-विमर्श के उपरंत आवश्यक कार्यों की पूर्ति एवं स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किए गए। खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल ने अधिकारियों को प्रस्तावित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने तथा स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी एवं जनहितकारी बनाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

## राष्ट्रगीत पर सियासत, भूपेश बघेल ने कहा-

**भाजपा ने आजादी के पहले नहीं गाया वंदे मातरम्**

**■ अजय चंद्राकर ने बहस के लिए दी खुली चुनौती**

रायपुर। राष्ट्रगीत वंदे मातरम् को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी तेज है। भाजपा और कांग्रेस एक-दूसरे पर हमलावर हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने आजादी के पहले वंदे मातरम् नहीं गाया। वहीं विधायक अजय चंद्राकर ने पलटवार करते हुए कांग्रेस की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए और भूपेश बघेल को बहस के लिए खुली चुनौती दे दी।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आजादी से पहले वंदे मातरम् गाने पर लोगों को गोली मार दी जाती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौर में भाजपा के लोग अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करते थे और उनके तलवे चाटते थे। बघेल ने भाजपा से सवाल किया कि आजादी से पहले भाजपा के किसी नेता ने वंदे मातरम् गाया था या आंदोलन के



हिस्सा लिया था क्या? भाजपा या आरएसएस के कार्यक्रमों में 'वंदे मातरम्' कब गाया गया?

बघेल ने कहा कि कांग्रेस के हर अधिवेशन में वंदे मातरम् गाया जाता रहा है। कांग्रेस ने ही इस गीत को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् के लिए कांग्रेसियों ने लाठियां और गोलायां खाई हैं

भूपेश बघेल के बयान पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल को जानकारी ही नहीं है कि कांग्रेस का वंदे मातरम् को लेकर क्या दृष्टिकोण रहा है। चंद्राकर ने सवाल किया कि कांग्रेस के

अधिवेशनों में क्या पूरा वंदे मातरम् गाया गया है? उन्होंने कहा कि वर्ष 1940 में कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम् गाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधते हुए चंद्राकर ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने वंदे मातरम् को स्वतंत्रता का मंत्र बताते हुए कहा था कि इसे गाया जाना चाहिए, लेकिन तत्कालीन पीएम नेहरू ने इसे स्वीकार नहीं किया।

अजय चंद्राकर ने कांग्रेस की वंदे मातरम् को लेकर भूमिका पर खुली बहस की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जगहिट के मुद्दों से कटकर अप्रासंगिक हो गई है। उन्होंने भूपेश बघेल की टिप्पणी को मानसिक विचलन करार देते हुए कहा कि पूरी कांग्रेस का यही हाल है। कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं है।

## बारिश में भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की खुल रही पोल : दीपक बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुये कहा कि बारिश में भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की पोल खुल रही है, नवनिर्मित पुल, पुलिया सड़के ही नहीं इस सरकार के भ्रष्टाचार के सबूत बह रहे हैं। राजनांदगांव, सुरजपुर, मुंगेली, गरियाबंद, रायगढ़ और कोरबा जैसे जिलों में नवनिर्मित पुलों और सड़कों के धंसेने, बहने या उनमें दरार आने के कई गंभीर मामले सामने आए हैं। उद्घाटन के तुरंत बाद या पहले ही निर्माण कार्यों में दरारें आने से भारी भ्रष्टाचार और घंटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल के हमारे द्वारा लगातार लगाए जा रहे आरोप प्रमाणित हो रहे हैं। रायपुर विशाखापट्टनम भारतमाला कॉरिडोर का 4146 करोड़ की लागत से छत्तीसगढ़ के हिस्से में तैयार सड़क उद्घाटन से पहले ही बारिश में जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो गया है, 20 से ज्यादा दरारें, सड़क और खलान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं, गुणवत्ताहीन



अंडरब्रिज दलदल बन चुका है।

**अन्य प्रमुख घटनाएं**

राजनांदगांव- 26 करोड़ रुपये की लागत से बने रेलवे ओवरब्रिज (बरगा और आलीवारा) उद्घाटन के महज 15 से 20 दिन बाद ही पहली बारिश में दरक गए और उनमें लंबी दरारें आ गईं।

सुरजपुर- धोंधा गांव में भारी बारिश के बाद पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है और आवाजाही बंद थी। गरियाबंद- गरियाबंद के उर्दाती क्षेत्र में निर्माणधीन पुल का हिस्सा बह गया

कोरबा- कोरबा के भैसामुड़ा में 3 करोड़ की लागत वाली पुलिया भी पहली बारिश नहीं झेल पाई।

मुंगेली में नया पुल बह गया,

रतनपुर पेंड्रारोड हाइवे पर रोज गाड़ियां फंस रही है, बस्तर और सरगुजा की सड़कों की स्थिति सर्वविदित हैं। रायगढ़ जिले के नवापारा में स्कूली बच्चों (जेन अल्फा) ने जर्जर सड़कों के खिलाफ कल गड़्डों में भरे पानी में नहाकर प्रदर्शन किया, पूरे प्रदेश में लगभग यही हालत है, मरम्मत तक नहीं करवा पा रही है सरकार।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मोदी सरकार ने संसद के इस सत्र में मिनरल संशोधन अधिनियम पारित किया है। इस संशोधन के अनुसार अब राज्य सरकारें अपने राज्यों से निकलने वाले खनिजों पर उपकर नहीं लगा सकती। छत्तीसगढ़ से कोयला, बाक्साईट, आयरन और जैसे-अनेकों खनिज निकलते हैं। अब हमारे राज्य से निकलने वाले खनिजों पर हम टैक्स नहीं ले सकते। कांग्रेस इसका विरोध करती है। मोदी सरकार ने अडानी को फायदा पहुंचाने यह कानून बनाया है।

## उपराष्ट्रपति के 2 सितंबर को प्रस्तावित छत्तीसगढ़

**प्रवास की तैयारियों की मुख्य सचिव ने की समीक्षा**

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में भारत के उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन के 2 सितंबर को प्रस्तावित छत्तीसगढ़ प्रवास की तैयारियों के संबंध में राज्य स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपराष्ट्रपति के प्रवास के दौरान सुरक्षा, प्रोटोकॉल, यातायात, चिकित्सा, स्वागत एवं कार्यक्रम स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन 2 सितंबर को रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे।

मुख्य सचिव श्री विकासशील ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन के प्रवास के दौरान सभी व्यवस्थाएं निर्धारित प्रोटोकॉल एवं मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम के अनुरूप सुनिश्चित



की जाएं।

उन्होंने एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक तथा वापसी के दौरान एंटी एवं एंजिट प्लान सहित सभी व्यवस्थाओं को बेहतर समन्वय के साथ अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने एयरपोर्ट पर स्वागत व्यवस्था, रिसेशन लाइन, एम्स में रिसेशन एवं अन्य प्रोटोकॉल संबंधी व्यवस्थाओं के लिए रायपुर कलेक्टर को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने एयरपोर्ट एवं कार्यक्रम स्थल पर पुलिस की समुचित तैनाती तथा

सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा।

मुख्य सचिव ने उपराष्ट्रपति के प्रवास के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए गृह विभाग को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही ठहरने की व्यवस्था, प्रकाश एवं विद्युत व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाएं तथा आकस्मिक चिकित्सा सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखते हुए सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने को कहा। बैठक में कार्यक्रम की बैठक व्यवस्था भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल एवं प्राप्त डायस प्लान के अनुरूप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम के

प्रारंभ में वंदे मातरम् एवं राष्ट्रगान सहित निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया।

मुख्य सचिव ने एम्स प्रबंधन एवं अधिकारियों को भी दीक्षांत समारोह के आयोजन से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत, मुख्यमंत्री के सचिव मुकेश कुमार बंसल, रायपुर कमिश्नर श्याम धावड़े, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के संयुक्त सचिव मयंक अग्रवाल, सामान्य प्रशासन विभाग की उप सचिव श्रीमती अंशिका पांडेय, कलेक्टर रायपुर, आईजी रायपुर, एम्स रायपुर के चिकित्सा अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

**कार्यालय प्राचार्य शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)**  
**रजबंध गैदान, रायपुर फोन 0771 2222990**  
www.govtdentalcollegeinraipur.in | Email: govtdentalcollege@gmail.com | GST-22BPS25701D2

क्रमांक /3849 / जीडीसी / क्रय / 2026 रायपुर, दिनांक 17/8/2026

**कैटीन संचालन हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (EOI)**

**तृतीय आमंत्रण सूचना**

आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 24/08/2026 समय 5.00 बजे तक

शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर परिसर में चिकित्सकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों एवं महाविद्यालय में उपचार हेतु आने वाले मरीजों के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण जलपान/भोजन/नास्ता आदि व्यवस्था हेतु कैटीन / कैफेटेरिया संचालन के लिये इच्छुक एवं योग्य व्यक्ति/फर्म/लाईवलीहुड/बिहान से पंजीकृत संस्था/स्व-सहायता समूह/एजेंसी / कंपनी / अनुभवी संचालकों से मैनूअल पद्धति में मोहर बंद प्रपत्र में रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) आमंत्रित की जाती है। विस्तृत जानकारी एवं नियम व शर्तें महाविद्यालय की वेबसाइट [www.govtdentalcollegeinraipur.in](http://www.govtdentalcollegeinraipur.in) से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकते हैं। इसके लिये राशि रुपये 1000/- का बैंक ड्राफ्ट जो प्राचार्य शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के नाम से देय हो संचालन करना अनिवार्य है अथवा दिनांक 24/08/2026, सायं 5.00 बजे तक राशि रु. 1000/- नाद अथवा बैंक ड्राफ्ट जमा कर महाविद्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं, जो वापसी योग्य नहीं होगी। विवरण निम्नानुसार है:-

प्रपत्र (EOI) जमा करने की अंतिम तिथि 24/08/2026 समय 5.00 बजे सायंकाल तक प्रपत्र (EOI) खोलने की तिथि 25/08/2026 समय दोपहर 12.30 बजे जमा करने व खोलने का स्थान शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर

**प्राचार्य शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर ( छ.ग. )**

**जी-262702830 /4**



# ज्ञानेश की तारीफ कर ट्रंप ने विपक्ष की बेचैनी बढ़ा दी

### नीरज कुमार दुबे

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की चुनाव व्यवस्था और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की तारीफ कर भारतीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। ट्रंप ने भारत में मतदाता पहचान की अनिवार्यता और विशाल स्तर पर चुनाव कराने की क्षमता का हवाला देते हुए अमेरिका में कड़े मतदाता पहचान नियम लागू करने की अपनी मुहिम को फिर हवा दी है। लेकिन इस बयान का असर केवल अमेरिका तक सीमित रहने वाला नहीं है। भारत में यह बयान चुनाव आयोग पर विपक्ष के आरोपों और सत्ता पक्ष की राजनीतिक रणनीति के बीच पहले से चल रही जंग को और तेज कर सकता है। हम आपको बता दें कि ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ट्वरूथ सोशल पर कहा कि ज्ञानेश कुमार ने अमेरिकी प्रशासन से पूछा था कि वैध फोटो पहचान पत्र के बिना अमेरिका में चुनाव कैसे हो सकते हैं? उन्होंने भारत के पिछले आम चुनाव में करीब 64 करोड़ 60 लाख मतदाताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि डाक से मतदान करने वालों की संख्या एक प्रतिशत से भी कम रही और मतदाताओं के लिए वैध फोटो पहचान पत्र जरूरी था। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका में मतदाता पहचान और नागरिकता से जुड़े कड़े नियम लागू करने वाले सेव अमेरिका अधिनियम को पारित करने की मांग दोहराई। ट्रंप का तर्क है कि मतदाता की पहचान और नागरिकता की कड़ी जांच चुनाव की विश्वसनीयता बढ़ा सकती है। हम आपको बता दें कि इस प्रस्तावित कानून में संघीय चुनावों के लिए पंजीकरण के समय नागरिकता का दस्तावेज, मतदान केंद्र पर फोटो पहचान और डाक से मतदान पर कड़े प्रतिबंध जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। अमेरिका में इस अधिनियम के विरोधियों का तर्क है कि गैर नागरिकों द्वारा चुनावी धोखाधड़ी बहुत दुर्लभ है और कठोर दस्तावेजी नियम उन पात्र मतदाताओं के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं जिनके पास पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। इस बीच, भारत में अमेरिकी रिजल्ट सर्जियो गोर ने ट्रंप के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि भारत के पिछले चुनाव में 64.6 करोड़ मतदाताओं के लिए पहचान पत्र की अनिवार्यता इस बात का मजबूत उदाहरण है कि अमेरिका को भी सेव अमेरिका अधिनियम लागू करना चाहिए। दूसरी ओर, ट्रंप के बयान के बाद भारत में राजनीति गरमा गयी है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ट्रंप के बयान को विपक्ष के चुनाव संबंधी आरोपों के खिलाफ मजबूत राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। सत्ता पक्ष का यह भी तर्क है कि दुनिया का एक प्रमुख नेता भारत की विशाल चुनावी व्यवस्था और मतदाता पहचान प्रणाली को उदाहरण के रूप में देख रहा है। वहीं ट्रंप के बयान के बाद विपक्ष के मतदाता सूची में गड़बड़ी, बड़े पैमाने पर मतधिकार से वंचित किए जाने और वोट चोरी जैसे आरोपों को हवा निकलती नजर आ रही है। ट्रंप की ओर से ज्ञानेश कुमार की प्रशंसा भारत में विपक्षी दलों को इसलिए भी नहीं पच रही क्योंकि वह संसद में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के अलावा उनके खिलाफ तमाम राजनीतिक आरोपों से लेकर निजी आक्षेप तक लगा चुके हैं। बदले हालात में विपक्ष यह तर्क दे रहा है कि किसी विदेशी नेता की प्रशंसा से भारत के भीतर चुनाव आयोग को लेकर उठे सवाल खत्म नहीं होते। विपक्ष विशेष गहन पुनरीक्षण यानि एसआईआर की कवायद और मतदाता सुविच्यों में कथित विसंगतियों को लेकर अपने आरोपों पर भी कायम है। वैसे भारतीय चुनाव आयोग पर हमलावर रहने वाले विपक्षी दलों की यह समझना होगा कि अपनी हार के कारणों पर मंथन करने की बजाय चुनाव आयोग पर ही सारा ठीकरा फोड़ देने से उन्हें सफलता नहीं मिलेगी।

### पुराण दिग्दर्शन ....

## विश्व विद्या-निरुपणाध्यायः ( दशम अध्याय )

( गतांक से आगे...)
अर्थात्- ग्रांच लगने से जिस प्रकार डेग का पानी ऊपर को उबलता है, इसी प्रकार चन्द्रमा के पूर्ण हो जाने पर श्राकर्षण से समुद्र का पानी भी उमड़ता है। प्रायः देखा जाता है कि समुद्र का जल 5१0 अंगुल के लगभग बढ़ता घटता है। पाठक विष्णुपुराण के शब्दों पर विचार करें कि उसमें ज्वारभाटे के सिद्धान्त का किस खूबी के साथ विवेचन किया है। यदि वर्तमान गवेषकों से पूछा जावे कि बतलाइये आप के अंग्रेजी मास की किस तारीख को ज्वारभाटा होता है? तो वे कुछ भी नहीं बता सकेंगे। क्योंकि उनकी तारीखों से चन्द्रमा का कोई भी सम्बन्ध नहीं है, अतः उन्हें लाचार होकर हमारी अष्टमी और पूर्णिमा की ही शरण लेनी पड़ेगी। साथ ही ज्वारभाटा किन्ता होता है? इसकी औसत भी श्री व्यास जी ने अतीव स्पष्ट शब्दों में ब्रता दी कि जिसे एक साधारण ग्राम्यजन भी बखूबी समझ सकता है।



वर्तमान गवेषक वर्षा के विषय में कहा करते हैं कि- सूर्य की उष्णता से पार्थिव जल वाष्प बन कर आकाश में फैल जाता है और समय पाकर मानसून हवा के संयोग से वही वाष्प ठिठुर कर कणशः होकर बरस जाती है।यदि हम उसे यह प्रश्न करें कि मेहरबान! जरा यह भी बताइये! कि आपकी मानसून हवाएं कब तशरीफ लाया करती हैं? और जब अकाल पड़ा करते हैं तब वे किस ब्लैक हाल में बन्द हो जाती हैं? तो बस वे बेचारे भारी असमञ्जस में पड़ जाएंगे क्योंकि अभी तक वे मानसून चलने की भविष्यवाणी करने में सर्वथा असमर्थ हैं। परन्तु पुराण-ग्रन्थों में इन प्रश्नों को बड़े ही सुन्दर और सरल ढंग से हल किया है, यथा –

विक्स्वानष्टभिर्मासैरादायापो रसात्मकाः।

वर्षत्यम्बु तदध्नान्नमन्नाद्रे चाखिलं जगत्।।

**क्रमशः ...**

# ईरान के चक्रव्यूह में फंसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप

### तनवीर जाफ़री

पूरे विश्व की निगाहें इस समय अमेरिका –ईरान के मध्य चल रहे तनावपूर्ण हालात पर लगी हुई है। इस्राईल के प्रधानमंत्री बेंजमिन नेतन्याहू ने अपने छल से राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान से एक ऐसे युद्ध में उलझा दिया है जिससे ट्रंप के लिये बड़ी परेशानी खड़ी हो गयी है। विश्व इतिहास में यह पहला मौका है जबकि ईरान जैसा देश प्रत्येक मोर्चों पर अमेरिका को बराबर की चुनौती दे रहा है। नतीजतन ट्रंप के ग़लत फैसलों से अब अमेरिकी सेना के जवान भी ऊब चुके हैं। पिछले दिनों अमेरिकी नौसेना के एक परमाणु ऊर्जा संचालित सुपर-कैरियर विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन CVN-72 को लेकर एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया।

यह युद्धपोत 21 नवंबर 2025 को सैन डिएगो, कैलिफ़ोर्निया से अपनी निर्धारित यात्रा पर निकला था। शुरुआत में इसे प्रशांत क्षेत्र और दक्षिण चीन सागर में तैनात किया जाना था, लेकिन जनवरी 2026 में इस्त्राईल –अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध छिड़ जाने के बाद इसे अचानक पश्चिम एशिया/अरब सागर की ओर मोड़ दिया गया। इस युद्धपोत पर लगभग 5,000 नौसैनिक और मरीन तैनात हैं। इन नौसैनिकों ने समुद्र में लगातार 250 से अधिक दिन बिताए हैं, जिसमें से करीब 200 दिन बिना किसी टॉप कॉल अर्थात बिना किसी बंदरगाह पर रुके हुये बीते हैं, जो आधुनिक अमेरिकी नौसेना के इतिहास में एक रिकॉर्ड है।

नौसैनिकों व मरीन की इस तैनाती को मूल रूप से मई 2026 में समाप्त होना था, लेकिन ईरान के साथ जारी जंग के कारण इसे बार-बार आगे बढ़ाया गया, जिससे सैनिकों की घर वापसी अनिश्चित हो गई। सैनिकों में पैदा हुये इसी अत्यधिक मानसिक दबाव के चलते कम से कम 6 नौसैनिकों ने युद्धपोत से समुद्र में कूदकर जान देने यानी आत्महत्या करने की कोशिश की, जिन्हें उन्हीं के सैनिक साथियों द्वारा समय रहते बचा लिया गया। इस घटना को लेकर



पूरी दुनिया में बड़ी चर्चा छिड़ गई है।

माइक लेविन जैसे कई अमेरिकी सांसदों और मरीन सैनिकों के परिवारों ने भी यह खुलासा किया कि युद्धपोत पर जीवन नरक जैसा हो गया है। कई हफ्तों तक जहाज़ पर गर्म पानी नहीं मिलता और टॉयलेट्स व शावर आदि खराब हो चुके हैं। लॉन्डी सुविधा बंद रहने से सैनिक गंदे कपड़े पहनने को मजबूर हैं। युद्धपोत पर भोजन और ज़रूरी सामानों की भारी कमी हो गई, यहाँ तक कि राशन कम होने पर सैनिकों को भोजन में बेहद कम व सीमित मात्रा दी जा रही है। और तो और युद्ध के कारण आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने से बहरान जैसे अमेरिकी ठिकानों से जहाज तक रसद पहुँचाना भी मुश्किल हो गया है। इस हादसे,अमेरिकी सांसदों के दबाव और परिवारों के आक्रोश के बाद अब अमेरिकी नौसेना के कार्यवाहक सचिव हंग काओ ने घोषणा की है कि युद्धपोत को अब रोटेशन प्लान के तहत वापस बुलाया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में इसकी जगह लेने के लिए दूसरे विमानवाहक पोत यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन को भेजा जा रहा है ताकि थके हुए सैनिकों को राहत मिल सके। परन्तु इस खबर ने वर्तमान समय में अमेरिकी सैनिकों की उबावपूर्ण स्थिति तो उजागर कर ही दी है।

### अशोक भाटिया

ऐतिहासिक लालकिले की प्राचीर केवल पत्थरों की एक संरचना नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्र भारत के उतार-चढ़ाव, उसकी आकांक्षाओं, उसकी नियति और उसके सामूहिक संकल्पों की मूक गवाह रही है। हर वर्ष 15 अगस्त को इस प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री जब राष्ट्र को संबोधित करते हैं, तो वह केवल एक औपचारिक भाषण नहीं होता, बल्कि वह आने वाले समय के लिए देश का नीतिगत और वैचारिक रोडमैप होता है। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी ऐतिहासिक प्राचीर से वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो अटूट संकल्प दोहराया है, वह देश की समकालीन राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज के लिए एक युगांतकारी मोड़ है। विकसित भारत का यह विजन महज एक राजनीतिक नारा नहीं है, बल्कि यह 140 करोड़ नागरिकों की सामूहिक चेतना को जगाने और उन्हें राष्ट्र निर्माण के एक महायज्ञ में आहुति देने के लिए प्रेरित करने वाला एक व्यापक राष्ट्रीय दर्शन है। जब हम इस विराट संकल्प की बात करते हैं, तो हमें इसके ऐतिहासिक संदर्भ और प्रासंगिकता को गहराई से समझना होगा। भारत ने लगभग दो सदियों तक औपनिवेशिक दासता और आर्थिक शोषण का दंश झेला है। 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ, तब हमारी अर्थव्यवस्था जर्जर थी, साक्षरता दर दुनियाय थी और अकाल तथा गरीबी जैसी बुनियादी चुनौतियां हमारे सामने थीं। शुरुआती दशकों में भारत का मुख्य ध्यान आत्मनिर्भरता और बुनियादी अस्तित्व की रक्षा पर था। हमने खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए हरित क्रांति की, अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए सैन्य तंत्र को मजबूत किया और धीरे-धीरे एक ठोस औद्योगिक आधार तैयार किया। आज, स्वतंत्रता के इस दौर में, भारत उस स्थिति से बहुत आगे निकल चुका है और अब हम केवल एक अस्तित्व बनाए रखने वाले देश नहीं हैं, बल्कि हम वैश्विक पटल पर एक नई दिशा तय करने वाले राष्ट्र बन चुके हैं। यह संकल्प इस बात का प्रतीक है कि अब भारत अपनी विकासशील छवि के खोल को तोड़कर वैश्विक शक्तियों की अग्रिम पंक्ति में खड़े होने के लिए पूरी तरह तैयार है। 2047 का वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारी स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष होगा, और कोई भी राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने पर



दुनिया के सामने अपनी सफलता का बया प्रमाण प्रस्तुत करता है, यही उसका वास्तविक ऐतिहासिक मूल्यांकन होता है।

इस व्यापक संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए देश के चार प्रमुख वर्गों को विकास का मुख्य केंद्र बिंदु बनाया गया है, जिन्हें युवा, महिला, किसान और गरीब के रूप में रेखांकित किया गया है। इन चारों स्तंभों के समग्र सशक्तिकरण के बिना किसी भी विकसित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। भारत आज दुनिया का सबसे युवा देश है और हमारी जनसांख्यिकीय लाभांश हमारी सबसे बड़ी ताकत है। विकसित भारत का सपना तभी सच हो सकता है जब इस युवा ऊर्जा को सही दिशा, उत्कृष्ट शिक्षा और वैश्विक स्तर का कौशल मिले। देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा को रोजगारीमुख बनाना इसी दिशा में उठाए गए बड़े कदम हैं। इसके साथ ही, विकसित भारत का दूसरा अनिवार्य पहलू महिलाओं का सशक्तिकरण और उनके नेतृत्व में होने वाला विकास है। जब तक देश की आधी आबादी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पूरी तरह सक्रिय नहीं होगी, तब तक विकास की रफ्तार अधूरी रहेगी। सेनाओं में महिलाओं की भागीदारी से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती महिलाओं की बढ़ती संख्या इस बात का प्रमाण है कि वे अब नीति निर्धारण के केंद्र में आ रही हैं। इसी तरह, भारत की आत्मा आज भी गांवों में बसती है और हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधार, आधुनिक खेती को बढ़ावा और वैश्विक कृषि आपूर्ति श्रृंखला में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना आवश्यक है। किसान जब पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर आधुनिक कृषि-उद्यमी बनेंगे, तभी ग्रामीण भारत समृद्ध होगा। अंत में, अंत्योदय की

## मानवता ही मनुष्य के कर्तव्य और जवाबदेही की सबसे बड़ी कसौटी

### कातिलाल मांडेत

हर वर्ष 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस केवल उन लोगों को स्मरण करने का अवसर नहीं है जिन्होंने युद्ध, हिंसा, प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकटों के बीच दूसरों की सहायता करते हुए अपने प्राण गंवाए, बल्कि यह हमें मनुष्य होने के अर्थ और हमारी जिम्मेदारियों पर विचार करने के लिए भी प्रेरित करता है। मानवता का वास्तविक मूल्य उस समय सामने आता है जब हमारे सामने किसी दूसरे व्य्क्ति का दुख हो और हम उसके प्रति संवेदनशील होकर सहायता का हाथ बढ़ाएं। मानवतावाद हमें यही सिखाता है कि मनुष्य की गरिमा, जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा किसी भी परिस्थिति में सर्वोपरि हैं। विश्व मानवतावादी दिवस की पृष्ठभूमि



अत्यंत मार्मिक है। 19 अगस्त 2003 को इराक की राजधानी बगदाद में संयुक्त राष्ट्र के कैनाल होटल पर हुए बम हमले में संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष दूत सर्जियो विएरा डी मेलो सहित 22 मानवीय सहायता कर्मियों की मृत्यु हो गई थी। ये लोग संकटग्रस्त लोगों की सहायता और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रहे थे। इस त्रासदी ने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर किया कि जो लोग दूसरों की रक्षा और सहायता के लिए संघर्ष क्षेत्रों में जाते हैं, उनकी सुरक्षा भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है। इसी घटना की स्मृति में

भावना के अनुरूप समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचना चाहिए, क्योंकि किसी भी राष्ट्र को तब तक विकसित नहीं कहा जा सकता जब तक कि बहुआयामी गरीबी का पूरी तरह उन्मूलन न हो जाए और हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन स्तर न मिल जाए।

आर्थिक मोर्चे पर, भारत आज दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और शीर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की ओर अग्रसर है। लेकिन विकसित देश बनने के लिए हमें केवल सकल घरेलू उत्पाद के आकार को ही नहीं बढ़ाना है, बल्कि प्रति व्यक्ति आय और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में भी गुणात्मक सुधार करना होगा। इसके लिए विनिर्माण और आत्मनिर्भरता पर विशेष बल देना आवश्यक है। मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारत आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, रक्षा उत्पादन और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है। रक्षा क्षेत्र में, जहां कभी हम पूरी तरह आयातों पर निर्भर थे, आज हम स्वदेशी अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों का निर्माण कर रहे हैं और उनका निर्यात भी बढ़ा रहे हैं। भारतीय कॉर्पोरेट जगत को अब वैश्विक कंपनियों की तुर्ज पर अपनी क्षमता का विस्तार करना होगा ताकि भारतीय ब्रांड दुनिया भर के बाजारों में अग्रणी भूमिका निभा सकें। इसके साथ ही, देश के बुनियादी ढांचे का कायाकल्प किया जा रहा है। आधुनिक रेलवे, एक्सप्रेसवे का विस्तृत नेटवर्क, जलमार्गों का विकास और हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण देश की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और व्यापार को सुगम बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। एक मजबूत और आधुनिक बुनियादी ढांचा ही विकसित भारत की ठोस नॉव बनेगा, जो देश के औद्योगिक विकास को नई गति प्रदान करेगा।

तकनीक और नवाचार के इस युग में जो देश अग्रणी रहेगा, वही दुनिया के भविष्य को दिशा देगा। भारत ने डिजिटल क्षेत्र में जो क्रांति की है, उसने दुनिया के विकसित देशों को भी अर्चषित किया है। हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल लेनदेन की व्यवस्था आज वैश्विक स्तर पर एक मिसाल बन चुकी है। भारत ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं है, बल्कि वह विश्व को सस्ती, सुरक्षित और समावेशी तकनीक देने वाला प्रदाता भी है। विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में बढ़ता

निवेश इस विजन को और स्पष्ट करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर मिशन, क्वांटम कंप्यूटिंग, अंतरिक्ष अनुसंधान और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत का बढ़ता कदम यह दर्शाता है कि हम भविष्य की तकनीकों के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर और संप्रभु होना विकसित भारत की एक अनिवार्य शर्त है, जो हमें वैश्विक मंच पर एक अद्वितीय पहचान दिलाएगी।

संकल्प जितना विराट होता है, उसकी राह की चुनौतियां भी उतनी ही कठिन होती हैं। विकसित भारत के मार्ग में कई आंतरिक और बाह्य चुनौतियां हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देश की आर्थिक प्रगति के साथ-साथ क्षेत्रीय और सामाजिक असमानता को पाटना एक बड़ी चुनौती है। विकास का लाभ समाज के हर वर्ग और देश के हर कोने तक समान रूप से पहुंचना चाहिए। इसके अलावा, भारत को पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच एक कुशल संतुलन बनाना होगा। जलवायु परिवर्तन के खतरों को देखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना युद्धस्तर पर आवश्यक है। प्रशासनिक स्तर पर, हमारी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-अनुकूल बनना होगा, क्योंकि लालफीताशाही और भ्रष्टाचार विकास की गति को धीमा करते हैं। वैश्विक मोर्चे पर, वर्तमान समय की भू-राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक व्यवधान भी हमारे सामने चुनौतियां खड़ी करते हैं, जिन्से निपटने के लिए भारत को अपनी कूटनीतिक कुशलता और आंतरिक आर्थिक सुदृढ़ता को निरंतर मजबूत बनाए रखना होगा।

निष्कर्षतः विकसित भारत का संकल्प केवल आर्थिक आंकड़ों या ऊंची इमारतों तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो आर्थिक रूप से समृद्ध हो, तकनीकी रूप से अग्रणी हो, सामाजिक रूप से समरस और न्यायपूर्ण हो, और संस्कृतिक रूप से अपनी समृद्ध जड़ों से जुड़ा हुआ हो। यह एक ऐसे भारत का सपना है जहां हर नागरिक को समान अवसर, उत्कृष्ट शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा मिले। लालकिले की प्राचीर से गुज़ा यह संकल्प देश के लिए एक महान आह्वान है। आने वाले दो दशक भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष होने जा रहे हैं।

### आज का इतिहास

- 1828 राजा राम मोहन रॉय के ब्रह्म समाज का पहला सत्र कलकत्ता (अब कोलकाता) में आयोजित।
- 1897 रीनाल्ड रॉस ने कलकत्ता (अब कोलकाता) के प्रेसिडेंसी जनरल हॉस्पिटल में काम करने के दौरान मलेरिया के कारक एनोफिलीज मच्छर की पहचान की।
- 1913 फ्रांस के एडोल्फ पेगोड पैराशूट के जरिए विमान से उतरने वाले पहले पायलट बने।
- 1921 केरल के मालाबार में मोपला विद्रोह की शुरुआत।
- 1944 राजीव गांधी का जन्म। वह देश के नौवें प्रधानमंत्री बने।
- 1955 मोरक्को और अल्जीरिया में फ्रांस-विरोधी दंगों में सैकड़ों लोग मारे गए।
- 1979 तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के 23 दिन बाद इस्तीफा दिया।
- 1988 पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक का हवाई दुर्घटना में निधन और सीनेट के सभापति गुलाम इशहाक खान राष्ट्रपति बने।
- 1988 सीतामढ़ी जंक्शन से होकर गुजरेगी भारत यात्रा गौरव टूरिस्ट ट्रेन, तीर्थ स्थलों का कराएगी दर्शन
- 1988 भारत और नेपाल में 6.5 की तीव्रता वाले भूकंप से एक हजार लोगों की मौत हुई।
- 1991 उत्तरी यूरोपीय देश इस्तोनिया ने तत्कालीन सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा की।
- 2002 फलस्तीनी छापामार नेता अबू निदाल मृत पाया गया।
- 2008 भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध कलाकार अरुणा साई राम को अमेरिका में विशिष्ट सम्मान से नवाजा गया।
- 2008 रसायन और उर्वरक मंत्री राम विलास पासवान ने खाद उद्योग को चालू वित्त वर्ष में 22,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देने की घोषणा की।
- 2012 बनेजुएला की राजधानी काराकस में दंगे में 20 लोग मरे।

2011 भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार राम शरण शर्मा की मृत्यु हो गई।

2013 उत्तरी काकेशस में रूसी पुलिस की कार्रवाई में नौ आतंकवादी मारे गए।

- 2018 अफगान बलों ने उत्तरी कुंडूज प्रांत में एक अभियान चलाकर तालिबान द्वारा कुछ घंटों पहले अगवा किए गए 149 लोगों के छुड़ाया।
- 2018 भारत की विनेश फोगाट ने जकार्ता एशियाई खेलों की महिला कुश्ती प्रतियोगिता के 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह देश की पहली महिला पहलवान बनीं।



# ट्रंप ने भारत की चुनाव व्यवस्था को सराहा, फिर भारत में उस पर सवाल क्यों?

## विनोद पाठक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की चुनाव व्यवस्था का उदाहरण देते हुए अपने देश में चुनाव सुधार की जरूरत बताई है। ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हुई बातचीत का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत जैसे विशाल देश में मतदाताओं की पहचान के लिए फोटो पहचान-पत्र की व्यवस्था है। चुनाव में बड़ी संख्या में लोग मतदान करते हैं। उन्होंने भारत में वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान पड़े 64.64 करोड़ वोटों और अपेक्षाकृत कम डाक मतपत्रों का भी संदर्भ दिया। ट्रंप का यह उल्लेख दरअसल अमेरिका में प्रस्तावित SAVE America Act के समर्थन में था, जिसमें मतदाता पहचान और नागरिकता के प्रमाण जैसी व्यवस्थाओं पर जोर दिया गया है।

ट्रंप का भारत की चुनाव व्यवस्था का उदाहरण देना अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसलिए नहीं कि भारतीय चुनाव आयोग को किसी विदेशी नेता के प्रमाण पत्र की जरूरत है, बल्कि इसलिए कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनावी व्यवस्था को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसी धारणा बन रही है, यह भी विचार का विषय है। लेकिन, इसी बंधु पर भारत की राजनीति का एक विचित्र विरोधाभास सामने आता है। जिस देश की चुनाव व्यवस्था को दुनिया का एक प्रमुख राजनीतिक नेता अपने यहां सुधार के लिए उदाहरण के रूप में देख रहा है, उसी देश में कुछ राजनीतिक दल चुनाव हारने के बाद उसी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हैं।

इनमें से कुछ दल ट्रंप के बयान पर भी सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद एवं मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने तो सोशल मीडिया पर ट्रंप को जवाब देते हुए यहां तक

लिख लिया कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता को अमेरिका ले जाइए और वहीं रख लीजिए। हमारी ईवीएम भी अगली उपलब्ध उड़ान से आपके पास भेज देंगे। आपने हमारी ओर जितने अपमान और तंज भेजे हैं, उनके बदले हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं।

दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप का तर्क मुख्य रूप से मतदाता पहचान और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता से जुड़ा है। अमेरिका में संघीय चुनावों के लिए मतदाता पहचान और नागरिकता के प्रमाण को लेकर उनकी सरकार लंबे समय से जोर दे रही है।

SAVE America Act में मतदाता पहचान, नागरिकता के प्रमाण और डाक मतपत्रों पर कुछ सीमाएं लगाने जैसे प्रावधान प्रस्तावित हैं। भारत में मतदाता की पहचान के लिए Electoral Photo Identity Card यानी EPIC मुख्य पहचान दस्तावेज है, हालांकि चुनाव आयोग निर्धारित अन्य पहचान दस्तावेजों को भी स्वीकार करता है। इसलिए यह कहना अधिक सही होगा कि भारत में केवल एक ही पहचान-पत्र से मतदान की व्यवस्था नहीं है, बल्कि EPIC के साथ आयोग द्वारा स्वीकृत वैकल्पिक दस्तावेज भी मान्य हैं। यही वह व्यवस्था है, जिसे ट्रंप अमेरिकी बहस में उदाहरण के तौर पर सामने रख रहे हैं। यहां सवाल ट्रंप की राजनीति का नहीं, अपितु भारत की व्यवस्था को लेकर हमारे अपने राजनीतिक रवैये का है।

भारत में चुनाव परिणाम आने के बाद एक परिचित राजनीतिक दृश्य देखने को मिलता है। जीत हुई तो जनता का आशीर्वाद, संगठन की मेहनत और लोकतंत्र की जीत, हार हुई तो ईवीएम, मतदाता सूची, चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल। यह स्थिति किसी एक दल तक सीमित नहीं रही है।

अलग-अलग समय पर अलग-अलग राजनीतिक दलों ने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल



उठाए हैं, लेकिन समस्या सवाल पूछने में नहीं है। लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है। समस्या तब पैदा होती है, जब सवाल का आधार ठोस प्रमाण के बजाय केवल चुनाव परिणाम बन जाता है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 97.98 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे और 64.64 करोड़ वोट पड़े।

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार इनमें 64.21 करोड़ ईवीएम वोट और लगभग 42.82 लाख डाक मतपत्र थे। इतने विशाल पैमाने पर चुनाव कराना अपने आप में दुनिया के सबसे बड़े प्रशासनिक अभ्यासों में से एक है। ऐसे में चुनाव आयोग से सवाल पूछना बिल्कुल जायज है, लेकिन सवाल और आरोप के बीच की सीमा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

ईवीएम पर राजनीतिक बहस नई नहीं है, लेकिन इस बहस में न्यायपालिका के निष्कर्ष को भी ध्यान में रखना चाहिए। अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट से संबंधित याचिकाओं पर फैसला देते हुए कहा था कि चुनाव प्रक्रिया में पर्याप्त जांच और संतुलन की व्यवस्था मौजूद है। केवल आशंका या अनुमान के आधार पर पूरी चुनाव प्रक्रिया को संदेह के घेरे में नहीं डाला जा सकता। अद्यतन ने 100 प्रतिशत वीवीपैट पर्वियों की गिनती को अनिवार्य करने की मांग भी

स्वीकार नहीं की। इसका अर्थ यह नहीं कि चुनाव आयोग आलोचना से ऊपर है। किसी भी लोकतांत्रिक संस्था को सवालों से परे नहीं माना जा सकता, लेकिन आलोचना और अविश्वास फैलाने के बीच अंतर जरूर होना चाहिए। अगर किसी राजनीतिक दल के पास चुनावी गड़बड़ी का ठोस प्रमाण है तो उसे निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से सामने रखना चाहिए। अदालत में जाना चाहिए, प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए और व्यवस्था में सुधार की मांग करनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि परिणाम मन के मुताबिक नहीं आया, पूरी मशीनरी को संदिग्ध बता देना लोकतांत्रिक विमर्श को मजबूत नहीं करता।

यहां विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। विपक्ष लोकतंत्र का अनिवार्य स्तंभ है। सरकार से सवाल करना, चुनाव आयोग से जवाब मांगना और मतदाता सूची की जांच करना विपक्ष का अधिकार ही नहीं, जिम्मेदारी भी है, लेकिन क्या यह जिम्मेदारी चुनाव परिणाम के साथ बदलनी चाहिए? क्या जिस चुनाव आयोग के माध्यम से कोई दल सत्ता में आता है, उसी आयोग की विश्वसनीयता अगले चुनाव में हारते ही संदिग्ध हो जाती है? क्या चुनाव आयोग तब तक निष्पक्ष है जब तक परिणाम हमारे पक्ष में है? क्या हार के बाद ईवीएम पर सवाल उठाना जनता के निर्णय पर सवाल उठाने के बराबर नहीं हो जाता? इन सवालों पर विपक्ष को आत्ममंथन करना चाहिए। चुनाव आयोग केवल कोई सरकारी कार्यालय नहीं है। वह संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित संवैधानिक संस्था है। देश के चुनावों के संचालन की जिम्मेदारी उसी के पास है। स्वयं चुनाव आयोग अपने नागरिक सेवा पोर्टल पर इसे चुनाव प्रशासन के लिए स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में वर्णित करता है।

ट्रंप ने तारीफ की तो क्या भारत को खुश

## जंग : दिमागी नक्सली और वन्दे मातरम् के बीच.....?

### ओमप्रकाश मेहता

देश की आजादी के आठ दशक बाद अब भारतीय राजनीति और उनके प्रणेताओं के भी सोच-विचार 'सटियाते' नजर आने लगे हैं, इसका मेरी समझ में एकमात्र कारण हमारी जिन्दगी के हर पहलू पर राजनीति का हावी होना है और राजनीति भी वह जिसमें 'स्वार्थ' का प्रतिशत सर्वाधिक है और इसी कारण राष्ट्रीय त्यौहार, पर्व हो या नीजी जिन्दगी हर कहीं केवल और केवल राजनीति ही नजर आने लगी है, इसका ताजा उदाहरण विगत स्वतंत्रता दिवस पर नजर आया, जहां एक ओर लाल किले की प्राचीर पर शायद पहली बार राजनीतिक प्रचार की तस्वीर नजर आई वहीं देश के प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस के मुख्यालय में ध्वज वंदन व राष्ट्रीय गान के वक अजीब नजारा सामने आया, ये दोनों ऐसे परिदृश्य हैं, जिसमें हमारे कर्णधारों की राजनीतिक सोच और उनके कर्म की झलक दिखाई दी और राष्ट्रीय गान के गंभीर माहौल में भी राष्ट्रीय अपमान के दर्शन हुए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी ने जहां लाल किले की प्राचीर से अपने तैरहवें सम्बोधन में अपनी पार्टी के प्रचार को हवा दी, वहीं प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस के मुख्यालय में ध्वज वंदन के समय पार्टी की सबसे अहम् तंत्री सोनिया गांधी ने अजीब दृष्य प्रस्तुत किया, जिसमें उनकी राह व राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान का परिमाण नजर आया। सत्तारूढ़ और प्रतिपक्षी प्रमुख दल के वरिष्ठ नेता मौजूदा सेवा भावना और अपनी राजनीति को कितना महत्व देते



है? यह भी स्पष्ट नजर आया।

....लेकिन इन परिदृष्यों ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हमारे कर्णधार नेताओं की सोच कितनी और आज उसकी दिशा किस तरफ है? आज देश का प्रबुद्ध वर्ग इन दोनों परिदृष्यों से काफी विचलित और दु:खी है और इसी विवाद में इस वर्ग को देश के भविष्य पर चिंतन के लिए मजबूर कर दिया है। अब वह सब हो रहा है, जो आजादी के बाद के अब तक के आठ दशकों में कभी नही हुआ। कांग्रेस के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने अठारह बार, उनकी बेटी इंदिरा जी ने सत्रह बार, डॉ. मनमोहन सिंह ने ग्यारह बार और स्वयं मोदी जी ने अब तक एक दर्जन बार लाल किले से ध्वज फहराया और देश को सम्बोधन किया, किंतु आज तक ये सम्बोधन कभी विवादित नही हुए? फिर यह आज क्यों हो रहा है, क्या अब राष्ट्रीय पर्व भी राजनीतियुक्त हो गए है? यह आज का सबसे अहम् चिंतनीय और चिंताजनक विषय है। इसलिए इस पर गंभीर चिंतन कर देश की नई दिशा की खोज जरूरी है।

## धुल गया संसद का मानसून सत्र: जवाबदेह कौन?

### पूनम आई. कौशिश

हमारे सांसद जिस काम के लिए चुने गए हैं, उसे छोड़कर बाकी लगभग हर काम हुआ। सत्र लगभग पूरी तरह धुल गया और महज 19 प्रतिशत संसदीय कामकाज ही हो सका। जरा सोचिए, कोई कर्मचारी 19 प्रतिशत काम करे और फिर भी पूरी तनख्वाह, भत्ते और सुविधाओं की उम्मीद रखे। किसी भी संस्था में यह अनुशासनात्मक कार्रवाई का कारण बन सकता है। लेकिन संसद में यह रोजमर्रा की बात हो गई है। हंगामा, नारेबाजी, स्थगन और आरोप-प्रत्यारोप के बाद लोकतंत्र पर गंभीर भाषण। निस्संदेह, विपक्ष को सरकार को घेरने और सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। सरकार को असहज सवालों का सामना करना ही चाहिए, क्योंकि संसद कभी भी रबर स्टैप बनने के लिए नहीं थी। लेकिन सरकार को जवाबदेह ठहराने और संसद को काम ही न करने देने के बीच बुनियादी अंतर है।

दुर्भाग्य से, संसद केवल बाधित नहीं हुई, बल्कि यह जिम्मेदारी से बेहद चिंताजनक पलायन का उदाहरण बन गई। सांसदों ने मानो लोकतंत्र के मंदिर को जवाबदेही से मुक्त किसी निजी क्लब की तरह समझ लिया। गौर कीजिए-लोकसभा ने 12 विधेयक पारित किए, जिनमें से 11 बिना बहस के पारित हुए और 9 के समय संबंधित मंत्री को छोड़कर कोई सांसद मौजूद नहीं था। केवल लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें 11 घंटे तक बहस चली और 48 सांसदों ने भाग लिया। दरअसल, संसद अपने सामने मौजूद एक बड़ी चुनौती का सामना करने में बुरी तरह विफल रही, जैन-काी द्वारा उठाए गए मुद्दों के लिए अपने दरवाजे खोलना और सड़क तथा संसद के बीच बढ़ती दूरी को पाटना। दूसरी ओर, विपक्ष को लगा कि



उसने एक बार फिर भाजपा से मुद्दे और राजनीतिक विमर्श की बढ़त छिन ली है। उसने प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ड्रशहसा पर बहस के लिए शाह की पेशकश को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि 'हम भाषण नहीं सुनना चाहते।'।

त्रासदी यह है कि हंगामा अब राजनीतिक रणनीति बन चुका है। राजनीतिक दल यह गणित लगाने लगे हैं कि संसद को बाधित करना, उसकी कार्यवाई की जांच-पड़ताल, बहस और सरकार को जवाबदेह बनाने से कहीं अधिक सोशल मीडिया फुटेज दिला सकता है। सदन में एक मिनट की नारेबाजी, विधायी कार्यों की एक घंटे की गंभीर और धैर्यपूर्ण पड़ताल से ज्यादा सुर्खियां बटोरती है। विचार-विमर्श की जगह नाटकीयता ने ले ली है और इसकी कीमत हम चुकाते हैं। संसद में बर्बाद हुआ हर घंटा केवल कोई संस्थागत आंकड़ा नहीं है। वह कनराताओं का पैसा है। वह लंबित कानून है। वह अनुसूचित सवाल है। वह ऐसी नीति है, जिस पर समुचित बहस नहीं हो पाती। वह संसदीय समितियों से छिन गया पड़ताल का अवसर है। और वह नागरिक हैं, जिन्हें बार-बार कतार में सबसे पीछे धकेल दिया जाता है। फिर भी किसी को थर्मिदगी महसूस होती नहीं दिखती। सबसे हैरान करने वाली बात है-संस्थागत जवाबदेही का पूरी तरह अभाव। समस्या किसी एक सत्र या किसी एक दल तक सीमित

## पश्चिम बंगाल सरकार के 100 दिन : भय से भरोसे तक

### के.के. उपाध्याय

सरकार के जीवन में 100 दिन बहुत लंबा समय नहीं होता। इतने कम समय में किसी राज्य की पूरी तस्वीर बदल भी नहीं सकती। लेकिन 100 दिन यह बताने के लिए पर्याप्त होते हैं कि सरकार की नीयत क्या है, नीति क्या है और दिशा क्या है। पश्चिम बंगाल की नई सरकार के पहले 100 दिन इसी कसौटी पर देखे जाने चाहिए। इन 100 दिनों की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल सरकारी फैसलों की लंबी सूची नहीं है। सबसे बड़ा परिवर्तन बंगाल के वातावरण में दिखाई देता है।

बंगाल लंबे समय तक राजनीतिक हिंसा, टकराव और भय की खबरों से पहचाना जाता रहा। गांव से शहर तक राजनीति जीवन के हर हिस्से में मौजूद थी। राजनीतिक पहचान कई बार व्यक्ति की सुरक्षा, अवसर और अधिकारों पर भी भारी पड़ती थी। नई सरकार के सामने पहली चुनौती इसी वातावरण को बदलने की थी। पहले 100 दिनों में सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया कि कानून का शासन होगा। राजनीतिक संरक्षण कानून से बड़ा नहीं होगा। इस संदेश का मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा है। लोकतंत्र का अर्थ है-बिना भय अपनी बात कहना। अपनी पसंद की राजनीति करना। प्रशासन के सामने शिकायत रखना। व्यापार करना। नौकरी करना। अपने परिवार के साथ सम्मान से जीना। जब नागरिक के मन से डर निकलता है, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है।

बंगाल में इसकी शुरुआत दिखाई दे रही है। असली परिवर्तन तब होता है, जब शासन की कार्य संस्कृति बदलती है। इन 100 दिनों में सरकार ने प्रशासन को स्पष्ट संकेत दिया है कि अब जवाबदेही सर्वोपरि है। फैसले समय पर हों। जनता की शिकायतें सुनी जाएं। योजनाएं कागज से निकलकर जमीन तक पहुंचें। सरकारी कार्यालय में सामान्य नागरिक को सम्मान मिले। फैसले लेने होंगे। परिणाम देना



होगा। फाइलों को चलना होगा। योजनाओं को धरातल पर उतरना होगा। शासन को जनता के दरवाजे तक पहुंचना होगा। सरकार ने शुरुआती 100 दिनों में स्वास्थ्य, रोजगार, महिला कल्याण, सीमा सुरक्षा और केंद्र-राज्य सहयोग जैसे क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाकर अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं।

नई सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को पश्चिम बंगाल में लागू करना प्रमुख है। इससे पात्र परिवारों के लिए सालाना 5 लाख रुपए तक के अस्पताल उपचार का रास्ता खुला है। इस योजना की बड़ी ताकत इसकी पोर्टेबिलिटी है। बंगाल का पात्र व्यक्ति देश के दूसरे हिस्से में भी सूचीबद्ध अस्पताल में इसका लाभ ले सकता है। इसलिए यह फैसला केवल एक योजना लागू करने का नहीं, यह आम परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा और मानसिक भरोसा देने का फैसला है।

पश्चिम बंगाल की बंगलादेश के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसलिए सीमा सुरक्षा यहां केवल एक प्रशासनिक विषय नहीं है। इसका सीधा संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा, घुसपैट, तस्करी, कानून-व्यवस्था और सीमावर्ती नागरिकों की सुरक्षा से है। नई सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बी.एस.एफ. को आवश्यक लॉबि भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में निर्णय लिया। यह एक

राजनीतिक और प्रशासनिक संदेश भी था-राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति नहीं होगी। केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे। सुरक्षा एजेंसियों को सहयोग मिलेगा। सीमा सुरक्षित होगी तो गांव सुरक्षित होंगे। गांव सुरक्षित होंगे तो बंगाल सुरक्षित होगा।

बंगाल ने लंबे समय तक केंद्र और राज्य के बीच राजनीतिक टकराव देखा है। इसका नुकसान अंततः जनता को ही उठाना पड़ता है। नई सरकार ने इस रिश्ते की भाषा बदलने का प्रयास किया है। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हो सकते हैं लेकिन विकास के प्रस्र पर दिल्ली और कोलकाता प्रतिद्वंद्वी नहीं, साझेदार होने चाहिए। रेलवे हो, राष्ट्रीय राजमार्ग हों, बंदरगाह हों, जलमार्ग हों, औद्योगिक कॉरिडोर हों, सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास हो या केंद्रीय कल्याणकारी योजनाएं, बंगाल की गति केंद्र और राज्य के सहयोग से कई गुना बढ़ सकती है।

सरकार की सबसे बड़ी पूंजी उसका बजट नहीं होता, उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है भरोसा। जनता का सरकार पर भरोसा, उद्योग का व्यवस्था पर भरोसा, निवेशक का नीति पर भरोसा, युवा का अपने भविष्य पर भरोसा, महिला का कानून पर भरोसा। इन 100 दिनों में यदि कोई एक परिवर्तन सबसे अधिक महसूस किया जा रहा है तो वह इसी भरोसे की वापसी है। इसे हर बार आंकड़ों में नहीं मापा जा सकता। यह बाजार की बातचीत में दिखाई देता है। उद्योग जगत की उत्सुकता में दिखता है। नौजवान की उम्मीद में महसूस होता है। सरकारी तंत्र के बदले व्यवहार में नजर आता है। राज्य तभी आगे बढ़ता है, जब नागरिक को विश्वास हो कि उसका आने वाला कल आज से बेहतर होगा। सरकार के सामने अपेक्षाएं बहुत बढ़ी हैं लेकिन अपेक्षाएं बढ़ी इसलिए हैं क्योंकि बंगाल की क्षमता भी असाधारण है। इन 100 दिनों में बंगाल की पूरी तस्वीर नहीं बदली है। लेकिन तस्वीर बदलने का विश्वास जरूर पैदा हुआ है। भय से भरोसे तक की यह यात्रा ही नए बंगाल की शुरुआत है।

## पंजाब में ‘बड़ा भाई’ कौन होगा?

### हरीश गुप्ता

छह साल पहले जब शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) अलग हुआ था, तब पंजाब में यह भाजपा का 'बड़ा भाई' था। भाजपा 117 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 23 पर चुनाव लड़कर छोटी सहयोगी पार्टी बन गई थी। हाल ही में मोदी और सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात ने अकाली-भाजपा के फिर से गठबंधन की अटकलों को हवा दे दी है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि इस बार बड़ा भाई कौन बनेगा? 2020 के बाद से बहुत कुछ बदल गया है। भाजपा ने पिछले छह वर्षों में पंजाब में अपना संगठन खड़ा किया है और 2022 के विधानसभा तथा 2024 के लोकसभा चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़े हैं। भले ही उसका चुनावी प्रदर्शन निराशाजनक रहा हो, लेकिन पार्टी अब किसी भी हालत में कनिष्ठ सहयोगी बनकर नहीं रहना चाहती। वह सीटों में काफी बड़ा हिस्सा चाहती है। वहीं, अकाली दल भी अधीनस्थ भूमिका स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह दिह्लों ने मोदी-बादल की मुलाकात का स्वागत किया, लेकिन साथ ही जोर देकर कहा कि भाजपा सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। निजी तौर पर भाजपा नेता मानते हैं कि एसएडी के साथ किसी भी नए गठबंधन का स्वरूप कृषि कर्षणों को लेकर टूटे पुराने गठबंधन से काफी अलग होगा। कांयून है कि औपचारिक गठबंधन के बजाय सीटों को लेकर कोई अनौपचारिक समझ बन जाए। इसके तहत भाजपा करीब 60-65 सीटों पर और अकाली दल लगभग 75 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, जिनमें से कई सीटों पर 'मैत्रीपूर्ण मुकाबला' देखने को मिल सकता है। विडंबना यह है कि दोनों दलों को एक-दूसरे की जरूरत है, लेकिन दोनों ही इसे स्वीकार करना नहीं चाहते। भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनावों में 18 156ब वोट मिलने के बावजूद एक भी सीट नहीं मिली, जबकि 2022 में उसे केवल दो विधानसभा सीटें मिलीं और 6 16ब वोट प्राप्त हुए। अकाली दल का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं

रहा। इसलिए, मजबूरी इन अलग-थलग पड़े साझेदारों को एक साथ ला सकती है - लेकिन बड़ा भाई कौन होगा, इसकी लड़ाई शायद चुनाव जितनी ही दिलचस्प होगी।

### एनडीए के सहयोगी अब खुलकर अपनी राह चुन रहे

एनडीए के भीतर एक नई बेचैनी पनपती दिख रही है, क्योंकि सहयोगी दल संकेत दे रहे हैं कि वे अब भाजपा के अधीन रहकर संतुष्ट नहीं रहना चाहते। इसका ताजा संकेत एनसीपीआई नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने दिया, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एनडीए का एक संयोजक नियुक्त करने की मांग की। इस मांग ने राजनीतिक हलकों को चौंका दिया है क्योंकि 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद से किसी भी सहयोगी दल ने सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। बंदोपाध्याय का तर्क है कि गठबंधन के भीतर संवाद और समन्वय बेहतर बनाने के लिए एक समर्पित संयोजक की जरूरत है, खासकर तब जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि न तो भाजपा और न ही टीडीपी या जेडीयू जैसे प्रमुख सहयोगी दलों ने इस पर कोई टिप्पणी की है। 20 लोकसभा सांसदों वाला एनसीपीआई, जो टीएमसी से आए सांसदों से बना है, अब ऐसे सहयोगियों के व्यापक समूह का हिस्सा माना जा रहा है जो गठबंधन में अधिक प्रभाव चाहते हैं। इसके संकेत अन्य जगहों पर भी दिखाई दे रहे हैं। बिहार में जद(यू) ने अपनी सीमाएं तय करना शुरू कर दिया है। सम्राट चौधरी सरकार के 550 से अधिक स्कूलों को मॉडल संस्थानों में बदलने, उनका नाम सरस्वती विद्या निकेतन रखने और उन्हें भ्रंगा रंग में रंगने के फैसले पर जद(यू) की आपत्ति सावधानीपूर्वक व्यक्त की गई, लेकिन स्पष्ट थी। जद(यू) के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, 'शिक्षा का केवल एक ही रंग होता है', जो शिक्षा के राजनीतिकरण को लेकर असहजता का संकेत था। वहीं दूसरी ओर, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू पर्दे के पीछे रहकर चुपचाप बातचीत करते हुए नतीजे हासिल करने में माहिर हैं।



# भगवती त्रिपुर भैरवी

ॐॐBCTI दुर्गा के अनंत नामों में से एक नाम महाविद्या है। वस्तुतः एक ही शक्ति अलग-अलग रूपों में अवतरित होकर अनेक प्रकार की लीलाएं करती है। आगमों की उपासना पद्धति में विशेष रूप से भगवति का त्रिपुर भैरवी नाम सर्वाधिक प्रतिष्ठित है। महाभागवत देवी पुराण में माता त्रिपुर भैरवी का विस्तृत वर्णन मिलता है। माहेश्वरी त्रिपुर भैरवी को त्रिपुर सुंदरी एवं षोडसी नाम से भी साधना की जाती है। शत्रुओं का दमन करने वाली, त्रिजगत को धारण करने वाली ये माताएं महाकाली के ही स्वरूप हैं। वाराही पुराण में वर्णित है कि ब्रह्मा, विष्णु व स्वयं शिव ने भी इनकी आराधना की थी। इसी लिए इनका नाम त्रिपुरा पड़ा।

### साधना के लाभ

त्रिपुर भैरवी की कृपा से साधक सिद्ध हो जाने पर समस्त प्रकार की सिद्धयां प्राप्त कर लेता है। उसकी सभी इच्छाएं व कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इससे साधक स्वयं ही आश्चर्यचकित रह जाता है। वह समस्त ज्ञान-विज्ञान व मंत्र विद्या में पारंगत होकर एक अद्वितीय पुरुष व तेजस्वी पुरुष बन जाता है। उसे भूतकाल व भविष्य का ज्ञान होने लगता है।

### दक्ष-नारद संवाद

देवी पुराण में कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा पुत्र दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया। हुआ यूं कि एक बार नारद जी दक्ष प्रजापति के पास पहुंचे और बोले, 'प्रजापते, आप जिन महेश्वर की प्रतिदिन निंदा करते हैं, वह उससे क्रोधित होकर जो करना चाहते हैं, उसे आप सुन लीजिए, वह अपने भूतगणों के साथ आपके निकट आकर आपको नष्ट कर देंगे।



आपसे स्नेह के कारण ही मैंने आपको सारी बात बताई है। इसे आप कभी किसी पर प्रकट न करें।' ऐसा कह नारद जी आकाश मार्ग से अपने स्थान लौट गए। इधर, दक्ष ने अपने मंत्रियों को बुलाकर समस्या उनके सामने रखी। तब मंत्री बोले, 'हे प्रजापति, हम देवाधिदेव शिव की इस अनीति का कारण नहीं समझा पा रहे। आप तो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ व सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं। आप ही कोई मार्ग सुझाएं।' तब दक्ष ने कहा, 'शमशान में निवास करने वाले भूतों के आधिपति शिव को छोड़कर आप सभी देवताओं को बुलाकर मैं यज्ञ का आयोजन करूंगा। समस्त विघनों का नाश करने वाले यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को यज्ञ का संरक्षक बनाकर इसे सफलता पूर्वक संपन्न करवाउंगा। इस प्रकार पुण्य यज्ञ का आरंभ हो जाने पर भूतपति शिव मेरे पुण्यकर्मयुक्त नगर में कैसे आ पाएंगे?'

### कैसे करें आराधना

त्रिपुर भैरवी की आराधना का समय रात्रि काल है। मंदिर में या किसी एकांत कमरे में आम से बना हुआ तथा लाल रंग से रंगा हुआ सिंहासन स्थापित करें। इस पर लाल वस्त्र बिछाकर भगवती त्रिपुर भैरवी का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। धूप-दीप जलाएं। स्वयं भी लाल वस्त्र पहनें, लाल रंग के फूलों का इस्तेमाल ही करें। फिर ध्यान मंत्र, मूल मंत्र व कवच मंत्र का पाठ करें।

**मूल मंत्र**– ॐ हस्त्रीं त्रिपुर भैरव्यै नमः मां के इस मंत्र का जाप 81 दिन में 5 लाख संपन्न करें। जप समाध्वत होने पर दशांश हवन करें। हवन के बाद आरती विसर्जन करें। 41 कन्याओं को मीठा भोजन करवाएं। साधना सिद्ध होने पर त्रिपुर भैरवी स्वयं आशीर्वाद देती हैं।

## विविध

किसी प्रेम को, आस्था को या समर्पण को जानना है, तो मीरा को जानना होगा। मीरा को जानना मोहन को पाने के बराबर है। कारण इसका यह भी है कि एक स्तर पर आकर उनका आपस का भेद ही खत्म हो जाता है...

# मीरा और मोहन

कृष्ण को जानना हो, तो मीरा को सेतु बनाओ, क्योंकि मीरा के अलावा दूसरा कोई सेतु नहीं जो कृष्ण को थाह पा सके। भक्त हर युग में हुए, मगर मीरा जैसा भक्त किसी युग में दूसरा नहीं हुआ। मीरा की कृष्ण भक्ति के आगे दुनिया की हर भक्ति फीकी दिखाई पड़ती है। मीरा कृष्ण जी की मूर्ति के सामने खड़ी होकर कहती हैं- ‘मैं तो सिर्फ इस योग्य हूँ कि तुम्हारे गीत गा सकूँ। इसके अलावा मुझमें दूसरा कोई गुण नहीं है। ‘*जहां बैठाने तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार-बार बलि जाऊं।’ अर्थात-* अब तो मेरा जीवन उसी की आज्ञा के जैसा चलता है। जहां बिठा देता है, वहीं बैठ जाती हूं। उठने को कहता है, तो उठ जाती हूं। मेरे तो प्रभु कृष्ण कहैया हैं, जिन पर जीवन बलिहारी है। परमात्मा के प्रति मीरा की दीवानगी इस हद तक थी कि उन्हें दुनिया में कृष्ण के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता था। वह कहती हैं, संतों के संग बैठ बैठ कर वह जो लोक लाज का वर्थ आड बर था, बोझ था वह सारा मैंने उतार दिया है। संत के संग बैठ कर भी अगर लोग लाज न खोई, तो संत से या सीखा?

### कौन थीं मीरा?

मीरा कृष्ण की दीवानी थी, ऐसा सारा संसार जानता है। मगर उनकी पृष्ठभूमि को जानना भी बहुत जरूरी है। मीरा का जन्म राठौर परिवार के रत्न सिंह और वीर कुंवरी के घर 1512 में मेड़ता में हुआ था। मीरा के दादा का नाम राव द्दा जी था, जो अत्यंत धनाढ्य थे। मीरा की माता वीर कुंवरी झाला राजपूत सुल्तान सिंह की बेटी थी। रत्न सिंह ने कुड़की गांव को अपना केंद्र बनाया था। मीरा ने गुरु गजाधर से शिक्षा ग्रहण की।



उन्हें अपनी आजीविका के लिए सात हजार बीघा जमीन दे रखी थी और उन्हें व्यास की पदवी से विभूषित किया था। मीरा की एक बाल सखी थी ललिता, जो वास्तव से उसकी दासी थी। एक बार मीरा महल के ऊपर खड़ी थी। नीचे से एक बारात जा रही थी। बाल सुलभ मीरा ने मां से पूछा कि यह क्या हो रहा है? मां ने बताया कि बारात जा रही है। मीरा के यह पूछने पर कि बारात क्या होती है? मां ने कहा कि वर पक्ष के लोग कन्या के घर पर उसे विवाह कर लातें हैं और विवाह में वर का किसी कन्या के साथ विवाह होता है। उसने मां से पूछा कि मेरा वर कौन होगा? इतने में कुल पुरोहित श्रीकृष्ण की एक मूर्ति लेकर आए और मां ने मजाक में कह दिया कि यह है तेरा वर। और मीरा ने श्रीकृष्ण को अपना वर मान लिया।

### जब मीरा की शादी हुई

मीरा जब शादी के योग्य हुईं, तो माता-पिता ने उनका रिश्ता राजकुंवर भोजराज से कर दिया। भोजराज

चितौड़ नरेश राणा सांगा के पुत्र थे। मीरा ने इसे अपनी दूसरी शादी करार दिया। राजघराने की बहू बनने के बाद भी वह हर वक्त श्रीकृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगीं। मीरा की एक देवरानी थी अजब कुंवरी, जो बाल विधवा थी। उसने मीरा की भावनाओं को समझ लिया तथा उसे सखी जैसा प्यार देने लगी। दूसरी तरफ उसकी ननद ऊदो ने बड़ी कोशिश की कि मीरा कृष्ण भक्ति छोड़ दें, मगर असफल रहीं।

राजकुंवर भोजराज की असमयिक मृत्यु हो गई। प्रथा के अनुसार पति की मृत्यु पर पत्नी को सती हो जाना था, मगर मीरा ने सती होने से इंकार कर दिया। सभी लोग चाहते थे कि मीरा सती हो जाए, मगर भोजराज का छोटा भाई मीरा के पक्ष में खड़ा हो गया और वह सती होने से बच गई।

### जब मीरा पर अत्याचार हुए

उसी समय बाबर ने भारत पर आक्रमण कर दिया। राणा सांगा और बार में भीष्म युद्ध हुआ, तो मीरा के पिता रत्न सिंह और भाई जलमल तथा अन्य रिश्तेदार राणा सांगा के साथ खड़े हो गए। मगर युद्ध में मारे गए, जिससे मीरा बहुत आहत हुईं। राणा सांगा भी मारा गया, तो चितौड़ की गद्दी पर राणा रत्न सिंह और उसके बाद विक्रम सिंह बैठे। विक्रम सिंह की बुरी नजर मीरा पर पड़ गई। उसने मीरा को प्राप्त करने का हर संभव प्रयास किया, मगर उसके इंकार करने पर वह मीरा से बदला लेने की सोचने लगा।

जन्माष्टमी के दिन राजा विक्रम सिंह ने मीरा को एक उपहार पेटिका भेजी, जिसमें काला भयंकर सांप था। मीरा ने पेटिका खोली, तो उस सांप को देखते ही पकड़ लिया। उसे कुछ नहीं हुआ। इतना ही नहीं, एक बार मीरा को धोखे से श्रीकृष्ण का चरणामृत कहकर विष भेजा गया। मीरा विष पीकर भी जिंदा रहीं। तब क्रोधित विक्रम सिंह ने मीरा पर तलवार से हमला किया, तो उसे एक साथ चार-चार मीरा नजर आने लगीं। आखिरकार मीरा अपने ताया के पास मेड़ता चली गईं, ताकि उसके अत्याचारों से बच सके। वह मथुरा वृंदावन भी गईं। और वहां के रणछोड़ जी के मंदिर में अपने बनाए भजन गाया करती थीं।

### मीरा समुद्र की लहरों में समा गईं

उधर राणा विक्रम अभी भी मीरा के पीछे पड़ा था। उसने पुरोहितों को मीरा के पास भेजा कि राणा बदल गया है। उसने यह भी कहलवा दिया कि अगर वह न लौटें, तो वह आमरण अनशन करेगा। मीरा ने समझ लिया कि अब प्रभु मिलन का समय आ गया है। वह समुद्र की लहरों की ओर बढ़ने लगीं और इस तरह 1573 में वह समुद्र की लहरों में समा गईं।

# व्यवसाय में उन्नति के लिए करें यह आसान उपाय



**सभी** चाहते हैं कि उनके व्यापार ि उन्नति हो और वे सफलता की सीढ़ियां ऋढ़ते जाएं। लेकिन व्यापार में भी उता-ऋढ़ाव आता रहता है यदि आप चाहते ि कि आपका व्यापार-व्यवसाय गगतातर तरक्की करता रहें तो यहां कुछ े शिष्ट उपायों का विवरण दिया जा रहा ि, जो अलग-अलग राशियों से संबंधित ि।

**मेष राशि:** -मेष राशि वाले यवसाय स्थल पर कांच या मिट्टी के ात्र में जल भरकर रखें। कांच के बर्तन ि थोड़ा पानी डालकर पांच सफेद फूल

रखें। पानी बदलते रहें। लोहे, स्टील या अन्य धातु, बॉटर कूलर, जग में पीने का पानी भरकर नहीं रखना चाहिए। मीठा खाकर जल पीकर प्रस्थान करना शुभकारी है।

**वृष राशि:** - वृष राशि वाले व्यवसाय स्थल पर चमकीले एवं हल्के रंगों का प्रयोग कर साज-सज्जा करें। दरवाजे के सामने के बजाए किसी कोने में बैठने का स्थान होना चाहिए।

**मिथुन राशि:** - मिथुन राशि वाले हरे पत्तों सहित फूल लाकर

अपनी दुकान या संस्था के ऑफिस में रखें। उत्तर या पूर्व की दीवार पर डॉल्फिन या पेंडुलम घड़ी अवश्य लगाएं। संस्थान के बाहर पांच हरे पौधे लगाएं। कार्यालय में आवाज करने वाला कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण न रखें।

**कर्क राशि:** - कर्क राशि वाले किसी पवित्र नदी या सरोवर का जल कांच के पात्र में भरकर दुकान के पूजाघर में रखें। इसके आलावा कार्यसिद्धि यंत्र अपने पूजा घर में रख प्रतिदिन दर्शन करें। पूर्णिमा को अपनी दुकान के प्रवेश द्वार के दोनों ओर कुछ गंगाजल अवश्य छिड़कें।

**सिंह राशि:** - सिंह राशि वाले अपने व्यवसाय स्थल में इस प्रकार बैठना चाहिए कि बाहर से व्यक्ति का मुंह दिखाई न पड़े। अष्टमी के दिन मिट्टी का शेर मंदिर में चढ़ाना चाहिए। लोहे या किसी भी धातु के फर्नीचर का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए।

**कन्या राशि:** - कन्या राशि वाले व्यापार शुरू करने से पहले दुर्गा चालीसा का पाठ करें। लकड़ी का फर्नीचर प्रयोग में लाएं। इसके आलावा व्यवसाय स्थल के सम्मुख गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं।

**तुला राशि:** - तुला राशि वाले जातकों को संस्थान के मध्य भाग में बैठना चाहिए। सात श्रीफल लाल वस्त्र में बांधकर कार्यस्थल की अलमारी में रख

दें। उस अलमारी में अन्य सामान नहीं होना चाहिए। शक्रवार के दिन से शुरू कर सुगंधित पुष्प लाकर पूजा घर में चढ़ाने चाहिए। मां दुर्गा के दर्शन कर फिर दुकान खोलें। दुकान में सजावट व स्वच्छता का बहुत ध्यान रखें।

**वृश्चिक राशि:** - वृश्चिक राशि वाले अपने व्यवसाय स्थल के मुख्य द्वार के दोनों ओर सिंदूर से स्वस्तिक बनाएं। दुकान के मंदिर में प्रथम मंगलवार, शनिवार को लाल पुष्प चढ़ाएं। कार्यस्थल पर आते समय किसी पूज्य व्यक्ति के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेकर आएँ। प्रत्येक मंगलवार गंगाजल लेकर दुकान के सभी कोनों में फूल द्वारा छिड़कें।

**धनु राशि:** - धनु राशि वाले कोष स्थान पर सफेद चंदन की लकड़ी हल्के गुलाबी रंग के कपड़े में लपेटकर रखें। दुकान के मंदिर में गाय के दूध से बने घी में छोटी इलायची डालकर दीपक जलाएं।

पीठ पीछे पूजा घर न बनाएं। मुख्य द्वार के सामने न बैठें। गुरुवार के दिन पीले फूल मंदिर में चढ़ाएं। गाय को रोटी-गुड़ खिलाएं।

**मकर राशि:** - मकर राशि वाले घोड़े की नाल मुख्य द्वार पर शाम के समय पीपल वृक्ष को छुआकर लगाएं। व्यापार बहुत मंदा हो गया हो तो

शनिवार को मिट्टी के घड़े पर दक्कन लगाकर, टेप से बंद कर दुकान में रख दें। बुधवार प्रातः काल उसे बहते जल में बगैर दक्कन खोले प्रवाहित कर दें।

**कुंभ राशि:** - कुम्भ राशि वाले कार्यस्थल में इस प्रकार बैठें कि आगे का स्थान खुला हो। कोई कोना या बंद दरवाजा न हो। शनिवार को मिट्टी के कुल्हड़ में मिट्टी का दक्कन रखें। उस दक्कन में 250 ग्राम काले तिल रखें तथा अगले दिन वह कुल्हड़ तिल सहित किसी को दान कर दें या पीपल पर रख आएँ। सजावट में लाल व सफेद रंग का प्रयोग न करें। शनिवार को दुकान पर आए भिखारी को खाली हाथ न लौटाएं।

**मीन राशि:** - मीन राशि वाले कार्यस्थल पर जाने से पूर्व पूज्य व्यक्ति के चरण स्पर्श व कार्यसिद्धि यंत्र के दर्शन कर घर से निकलना चाहिए। गुरुवार को पीला फल लाकर कार्यस्थल के पूजाघर में रखें, दूसरे दिन उसे किसी भिखारी को दान दें।

गुरुवार के दिन कार्यस्थल पर आए हुए साधु को दान अवश्य दें। सफेद चंदन को पीले वस्त्र में बांधकर नवरात्र की नवमी को दुकान की तिजोरी में रखें। बुधवार को पीला पपीता खिलाएं।

व्यक्ति उपासना, प्रायश्चित्त कर्म के माध्यम से मुक्ति अवश्य प्राप्त कर सकता है.

**पूर्वजन्मकृत किसी श्रापादि जन्म दुष्प्रभाव से मुक्ति का सहज उपाय :**-

प्रत्येक महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, जिसे कि मास-शिवरात्रि भी कहा जाता है.

वर्षप्रयन्त यदि उस दिन उपावास रख, शिवलिंग पर चन्दन, जल, दूध, शहद,व बेलफल अर्पित करने तथा स्व इच्छित संख्या में ‘ ए ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं ? ‘ का जाप किया जाए. तत्पश्चात त्रिधातु (सोना, चाँदी, ताँबा मिश्रित) काल्ला अनामिका अंगुली में धारण करें एवं रात्रि समय सोने से पूर्व कुछ समय जाने अनजाने में किए गए किन्ही अपराधों की क्षमाप्रार्थना कर श्री महामृत्युंजय मन्त्र का जाप किया जाए तो पूर्वजन्मकृत कई प्रकार के दोषों से सहज ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है.

# अनेकानेक बाधाओं से मुक्ति मात्र सिर्फ एक उपाय से.....

**कर्म** करना एक तरह से मानव जीवन की विवशता ही है, क्यों कि किए गए कर्मों से ही प्रारब्ध का निर्माण होता है. भाग्य पूर्व के संचित कर्मों तथा वर्तमान जीवन के किए गए कर्मों के मिश्रण का ही रहस्यमयी अंश है.

इसलिए अधिकतर लोग अपने-अपने क्षेत्रों में सफलता के चरम को छूने के लिए निरन्तर संघर्षशील रहते हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम ही अपने सपनों को हकीकत में बदल पाते हैं. ऐसी मान्यता है कि प्रकृति केवल योग्य ‘प्रारब्ध’ का ही स्वागत करती है. यहाँ योग्य शब्द विज्ञान के किसी भी तर्क तथा मानव बुद्धि की

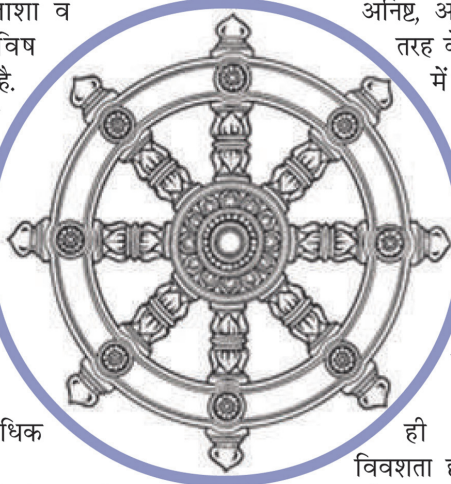
सीमा से बाहर है. ‘योग्यता’ के बीज कर्मफल में ही छिपे रहते हैं और इन बीजों में लुप्त रहतपनी चेतना में समेटे आत्मा इस शरीर में जन्म लेती है. किसी व्यक्ति की जन्मकुंडली में वरदान धनयोग, राजयोग, महापुरुष योग आदि कई प्रकार के योगों के रूप में उभरता है तथा अपनी दशा अनुसार व्यक्ति की दृष्टि, बुद्धि, विवेक तथा पुरुषार्थ को सफलता, सम्पन्नता, ऐश्वर्य, सुख तथा यश-मान, प्रसिद्धि की ओर अग्रसर करता है.

दूसरी ओर किसी की जन्मकुंडली में श्राप अद्भुत रूप से उसके जीवनकाल में किए जा रहे क्रियामान प्रयत्नों(कर्मों) में अवरोध,

निराशा, हताशा व दुःख का विष घोलता रहता है.

यही एक ज ि ट ल रहस्य है, जो हमें बताता है कि क्यों हममें से कुछ लोग ओरों की अपेक्षा अधिक

भाग्यशाली, सफल व सुखी जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, कुछ थोड़े से प्रयत्न से ही



ही जीवन की विवशता हो, परन्तु पूर्व जन्म के अधिकतर दोषों, अपराधों यथा किन्ही श्राप आदि से



**आपका** व्यवसाय निरंतर प्रगति करता रहे इसके लिए यदि आप चाहें तो निम्न सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं।

■ व्यावसायिक स्थल का उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र ( ईशान कोण) हमेशा साफ-सुथरा और खाली रहे। यहां पूजाघर बनाएं या पेयजल की व्यवस्था कर सकते हैं।

■ व्यावसायिक स्थल के मालिक दक्षिण दिशा में इस प्रकार बैठें कि उनका मुंह उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रहे।

■ ग्राहकों को हमेशा वायव्य या पश्चिमी दिशा में बिठाएं या खड़ा रहने दें।

■ वह सामान जो काफी समय से स्टॉक में है, बिक नहीं रहा है उसे उत्तर-पश्चिम की तरफ रखें।

■ भारी सामान, भारी मशीनरी, कबाड़ इत्यादि को दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य) में रखें।

■ व्यवसाय स्थल के मुख्य द्वार के सामने कोई खंभा, बड़ा पेड़, बिजली का ट्रांसफॉर्मर इत्यादि नहीं हो। यदि ऐसा है तो मुख्य द्वार के बाहर उत्तल अथवा बगुआ दर्पण इस प्रकार लगाएं कि इनका प्रतिबिंब दर्पण में दिखे।

■ मुख्य द्वार के ऊपर बाहर या अंदर की ओर देखते हुए गणेशजी की प्रतिमा, अपने ईष्ट देव या धार्मिक प्रतीक चिह्न लगाएं।



### चुनाव से पहले तावड़े को यूपी बीजेपी का प्रभार



नईदिल्ली। बीजेपी ने पार्टी संगठन में बड़ा बदलाव करने के साथ ही चुनावी राज्यों में नई नियुक्तियां कर दी हैं. पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस ली है. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीनी की अगुवाई में घोषित नई राष्ट्रीय टीम में कई नए चेहरों को जगह दी गई है, वहीं चुनावी राज्यों की जिम्मेदारी अनुभवी नेताओं को सौंपी गई है.

पार्टी ने विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है. उनके साथ जगदीश ईश्वरभाई पटेल को सह-प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है. तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद हैं. उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है, ऐसे में संगठन की कमान तावड़े को सौंपना अहम माना जा रहा है.वहीं सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है. पुनिया भी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद हैं।

### टनल धंसने से अब तक 10 मजदूरों की मौत



निकाल लिया है. इस हादसे में कुल 10 मजदूरों की जान चली गई है, जबकि 12 लोग घायल हो गए. मंगलवार को टनल से दो मजदूरों के शव निकाले गए. इनकी पहचान झारखंड के खूंटी जिले के रहने वाले 31 वर्षीय लुकास टोपनो और छत्तीसगढ़ निवासी चेतन पोयाम के रूप में हुई है. ये हादसा 13 अगस्त 2026 की शाम को टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की निर्माणाधीन विष्णुगाड-पीपलकोटी जलविद्युत परियोजना की सुरंग में भूस्खलन के कारण हुआ था. मलबे और पानी के अचानक भरने से 3 किलोमीटर लंबी सुरंग में कुल 22 लोग फंस गए थे।

### सेना ने दहशतगर्दों का इकोसिस्टम तबाह किया

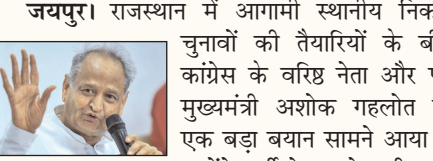
जम्मू। ऑपरेशन महादेव से लेकर शाहजाद भट्टी नेटवर्क तक, एक साल में सेना ने जम्मू-कश्मीर में 34 बड़े ऑपरेशन चलाए. चिनार और व्हाइट नाइट कोर ने घुसपैठ रोकी, ठिकाने तोड़े और आतंकियों को खत्म किया.अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ एक सतत और आक्रामक अभियान शुरू किया. जुलाई 2025 में ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम हमले के तीन आतंकियों को डाकिंगाम क्षेत्र में खत्म कर दिया गया. यह संयुक्त अभियान था जिसमें सेना की 4 पारा, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस शामिल थीं. इस सफलता के बाद सुरक्षा बलों का फोकस सिर्फ प्रतिक्रिया देने से बदलकर आतंकियों, उनके सपोर्ट नेटवर्क और घुसपैठ मार्गों को व्यवस्थित रूप से खत्म करने पर आ गया. आजतक द्वारा प्राप्त ऑपरेशनल रिकॉर्ड्स के अनुसार पिछले एक साल में चिनार कोर (कश्मीर) और व्हाइट नाइट कोर (जम्मू) ने लगभग 34 महत्वपूर्ण काउंटर-टेरर और एंटी-इन्फिल्ट्रेशन अभियान चलाए।

### राहुल ने रिजिजू के बयान पर पलटवार किया



नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली पुलिस और प्रशासन का बचाव करते हुए कहा कि इतने बड़े प्रदर्शन को बिना किसी गंभीर चोट या जनहानि के संभालना सराहनीय है. वहीं विपक्ष ने सरकार के इस दावे पर सवाल उठाते हुए प्रदर्शनकारी छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रिजिजू के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि, मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी चाहिए. संसद से आधा किलोमीटर दूर, शांतिपूर्ण छात्रों पर पैलेट गन चली, कील लगी लाठियां चलीं, एक बच्चे की आंख चली गई, एक बच्ची का मंत्री कह रहा है कि दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी चाहिए? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, मैं खुद उन घायल बच्चों से मिला हूं. हजारों वीडियो देश ने देखे हैं।

### जेन-जी को दीजिए 50 प्रतिशत टिकट: गहलोत



जयपुर। राजस्थान में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने पार्टी नेतृत्व से अपील की कि इस बार निकाय चुनावों में 50 प्रतिशत से ज्यादा टिकट ‘Gen-Z’ और युवा उम्मीदवारों को दिए जाने चाहिए, मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि इस समय पूरे देश में एक नया दौर शुरू हो रहा है और नई पीढ़ी आगे आ रही है. इस बदलाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.उन्होंने कहा, मैंने ये सुझाव दिया है कि युवाओं और ‘Gen-Z’को आधी से ज्यादा टिकट दिए जाएं. नई पीढ़ी के आने से पूरे देश में बदलाव का माहौल बन रहा है. गहलोत ने हाल ही में दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलनों और प्रधानमंत्री आवास के पास राहुल गांधी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों का जिक्र किया. उन्होंने कि ये घटनाएं बताती हैं कि देश में पीढ़ीगत बदलाव हो रहा है. उनके मुताबिक वरिष्ठ नेताओं के अनुभव का इस्तेमाल जारी रहना चाहिए।

# महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक आज

## गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहाकारिता मंत्री अमित शाह 20 अगस्त को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, तेलंगाना राज्य और पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र शामिल हैं। सभी राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से पिछले लगभग बारह वर्षों में (जून 2014 से अब तक) विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों और इनकी स्थायी समितियों की कुल 69 बैठकें आयोजित हुई हैं।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 से 22 के तहत दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद सहित पांच क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहाकारिता मंत्री अमित शाह दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय इसके उपाध्यक्ष हैं।

सदस्य राज्यों में से एक राज्य के मुख्यमंत्री बारी-बारी से परिषद के उपाध्यक्ष होते हैं। 31वीं बैठक अंतर-राज्य परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तमिलनाडु सरकार की मेजबानी में आयोजित की जा रही है। इसमें दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्यमंत्री/उप-राज्यपाल/प्रशासक के साथ-साथ प्रत्येक राज्य से दो वरिष्ठ मंत्री भाग



लेंगे। राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/सलाहकार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहेंगे।

क्षेत्रीय परिषद ने मुख्य सचिवों के स्तर पर एक स्थायी समिति का भी गठन किया है। राज्यों द्वारा प्रस्तावित मुद्दों को पहले क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति के समक्ष चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें विचारों होने के बाद शेष बचे मुद्दों को क्षेत्रीय परिषद की बैठक में विचार के लिए प्रस्तुत किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारी संघवाद के आधार पर देश के सामने टीम भारत की कल्पना रखी है और क्षेत्रीय परिषदें इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

क्षेत्रीय परिषदें मजबूत राज्य ही मजबूत राष्ट्र बनाते हैं की भावना से काम करती हैं। परिषदें दो या अधिक राज्यों अथवा केंद्र और राज्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर, संवाद

और चर्चा के लिए एक व्यवस्थित तंत्र, तथा इसके जरिये आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए मंच प्रदान करती हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में क्षेत्रीय परिषद की बैठकें संवाद से समाधान का सशक्त मंच बनी हैं। क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका सलाहकारी है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये परिषदें विभिन्न क्षेत्रों में आपसी समझ और

सहयोग के स्वस्थ बंधन को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कारक साबित हुई हैं। क्षेत्रीय परिषदें, केंद्र और सदस्य राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के बीच, सदस्य राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के मध्य, तथा क्षेत्र के मुद्दों और विवादों को हल करने और उन पर प्रगति लाने के लिए एक श्रेष्ठ मंच प्रदान करती है।

ये परिषदें, राष्ट्रीय महत्व के व्यापक मुद्दों पर भी चर्चा करती हैं, जिनमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म के मामलों की त्वरित जांच और इनके शीघ्र निपटान के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों का कार्यान्वयन और शिक्षा से संबंधित मुद्दे आदि शामिल हैं। साथ ही क्षेत्रीय स्तर के सामान्य हित के विभिन्न मुद्दे जैसे आन्ध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम से सम्बंधित मुद्दे, जल बंटवारे से सम्बंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं के मुद्दे, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, नागरिक उड्डयन से सम्बंधित मुद्दे, आदि शामिल हैं।

### केन-बेतवा प्रोजेक्ट, आदिवासियों का दमन असहनीय : राहुल गांधी

नईदिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का विरोध कर रहे बुंदेलखंड के आदिवासी निवासियों का समर्थन किया है। ये आदिवासी उचित मुआवजे और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। 19 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में गांधी ने कहा कि हमारे आदिवासी भाई-बहनों की इस लड़ाई में, मैं और कांग्रेस उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने आदिवासी निवासियों की आपबीती साझा करते हुए कहा कि केन-बेतवा परियोजना के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे आदिवासी भाई-बहनों की समस्याएं, मांगें, संघर्ष और निजी परेशानियां डूब उठीं की जुबानी।

गांधी ने आगे कहा कि बुंदेलखंड के ये निवासी सालों से सिर्फ अपने अधिकारों के लिए अन्याय और दमन सह रहे हैं; वे सम्मान और समर्थन के हकदार हैं। इससे पहले जुलाई में, गांधी ने एक्स पर एक कविता और तस्वीरें पोस्ट की थीं, जिसमें उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से उचित मुआवजे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों का जिक्र किया था और आदिवासी लोगों को देश का असली मालिक बताया था। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वह सच और अहिंसक विरोध, दोनों से डरती है, और अगस्त की शुरुआत में छतरपुर में पुलिस की कार्रवाई की निंदा की।

गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई-बहन जल सत्याग्रह और भूख हड़ताल पर बैठे थे क्योंकि केन-बेतवा परियोजना के लिए उनकी ज़मीन ले ली गई थी, लेकिन उन्हें न तो उचित मुआवज़ा मिला और न ही सम्मानजनक पुनर्वास। सच यह है कि आदिवासी देश के असली मालिक हैं- पानी, जंगल और ज़मीन पर पहला अधिकार उन्हीं का है। और उनका सत्याग्रह इसलिए है क्योंकि आज उनसे वही अधिकार छीना जा रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि अपने अनोखे अंदाज़ में, उनकी मांग बस यही है: उन्हें रोज़ी-रोटी का सही ज़रिया दिया जाए- वरना जिंदगी चिता से अलग नहीं है। लेकिन बीजेपी सरकार को यह भी मंजूर नहीं है। उनकी बात सुनने के बजाय, पुलिस बल का इस्तेमाल करके उनके शांतिपूर्ण विरोध को दबाया जा रहा है। हम अपने आदिवासी भाई-बहनों के साथ खड़े हैं। हम उन्हें न्याय दिलाकर रहेंगे।



### स्टील प्रमुख समाचार

### भारत ने श्रीलंका को पहले टेस्ट मैच में 165 रन से हराया

गॉल। भारत ने गॉल में श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ के पहले मैच में 165 रनों से आसान जीत हासिल की। जीत के लिए मिले 372 रन के लक्ष्य के जवाब में



श्रीलंका की दूसरी पारी 206 रन पर सिमट गई। मानव सुधार ने छह विकेट लिए। इस जीत के साथ टीम इंडिया दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है। सीरीज का दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा।

पांचवें दिन स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाने का दबाव धनंजय और सोनल दिनुशा पर था और वे काफी हद तक ऐसा करने में सफल भी रहे। हालांकि, लंच से ठीक पहले रवींद्र जडेजा ने टीम को ज़रूरी सफलता दिलाई और धनंजय 59 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद जिम्मेदारी सोनल और नए बल्लेबाज निरोशन डिकवेल्ला पर आ गई। इनमें से सोनल ने संयम बनाए रखा और श्रीलंका की उम्मीदें जिंदा रखीं, लेकिन यशस्वी जायसवाल की बातों से परेशान होकर डिकवेल्ला 10 रन पर आउट हो गए। भारत के युवा ओपनर ने विकेटकीपर-बल्लेबाज को उकसाते हुए कहा कि अगर वह छक्का मारते हैं तो उन्हें आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है; हो सकता है कि इसी वजह से वह आउट हो गए हों।

दूसरी पारी में मानव सुधार का दबदबा रहा। इस सप्तिनर ने कहर बरपाते हुए छह विकेट लिए। उन्होंने मैच की अपनी आखिरी 10 गेंदों में चार विकेट चटकाए और भारत को आसान जीत दिलाई। श्रीलंकाई बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनका सामना कैसे करें, और नतीजा यह हुआ कि उनकी पारी जल्दी सिमट गई। वहीं, इसका श्रेय सोनल को भी जाता है, जिन्होंने दूसरी पारी में 84 रन बनाए। उन्होंने यहाँली पारी में भी शतक जड़ा था, जिससे साबित हुआ कि वह खेल के सबसे लंबे फॉर्मेट में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं।

## आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/

## प्रमुख समाचार

# भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, पर कुछ चुनौतियां भी हैं

#### जयंतীलाल भंडारी

हाल ही में वैश्विक रेटिंग एजेंसी ‘फिच रेटिंग्स’ ने भारत की सॉबरेन रेटिंग को ‘बीबीबी माइनस’ पर स्थिर परिदृश्य के साथ यथावत रखा है। फिच ने कहा है कि वैश्विक तनावों और तेल बाजार के उतार-चढ़ाव का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई दीर्घकालिक या स्थायी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। भारत ने वैश्विक झटकों का सफलतापूर्वक सामना किया है और सकारात्मक आर्थिक वृद्धि बनाए रखी है। फिच ने रेटिंग तय करते समय नीतिगत विश्वसनीयता, बाहरी वित्तीय ढांचे और ऋण वहन करने की क्षमता का विस्तृत विश्लेषण किया है।

भारत के मामले में इन सभी मानकों पर सकारात्मक स्थिति देखने को मिली है। निरंतर सुधरती नीतिगत विश्वसनीयता और सुदृढ़ आर्थिक नीतियों ने देश की बाजार क्षमता को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाया है। उच्च

विकास दर के बल पर सरकार के कुल ऋण अनुपात को नीचे लाने में सफलता मिल रही है, जो वित्तीय साख को मजबूती प्रदान करती है। 2026-27 के बजट में ऋण-जीडीपी अनुपात 55.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 56.1 फीसदी से बेहतर स्थिति है। सरकार का लक्ष्य मार्च 2031 तक इसे घटाकर 50 प्रतिशत पर लाना है।

उल्लेखनीय है कि एसएंडपी ग्लोबल ने भी भारत की दीर्घकालिक साख को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ ‘बीबीबी माइनस’ श्रेणी में रखा है। इसका मुख्य आधार भारत का शानदार आर्थिक प्रदर्शन और सरकार की सुदृढ़ नीतिगत दिशा है। मूडीज रेटिंग्स ने भारत की साख को स्थिर दृष्टिकोण के साथ ‘बीएए3’ के स्तर पर रखा है, जो सुरक्षित निवेश श्रेणी का परिचायक है। इन साख निर्धारणों के मूल में भारत का मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, घरेलू मांग में जारी तेजी और



संतुलित बैंकिंग प्रणाली है। हालांकि, उच्च सरकारी कर्ज और राजकोषीय घाटा अब भी साख सुधार में बाधक हैं, जिनसे निपटने के प्रयास जारी हैं।

भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मजबूत घरेलू संकेतों के आधार पर विकास दर के अपने अनुमान को बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दिया है, जबकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने इसे 6.4 प्रतिशत पर आकलित किया है। भारत की विकास दर को गति देने में तीन प्रमुख कारकों की मुख्य

### असीम संभावनाओं वाला यूपी दूसरा घर बनाएँ जापानी कंपनियाँ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि राज्य में अपार संभावनाएँ हैं, यह लगातार तर्कही कर रहा है और भारत की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने जापान को राज्य में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। इस बात पर जोर देते हुए कि दोनों देशों की मूल्य-मान्यताएं समान हैं, उन्होंने कहा कि भारत-जापान की साझेदारी विकास, तकनीक और समृद्धि की साझेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि जापानी कंपनियां उत्तर प्रदेश को अपना दूसरा औद्योगिक घर बनाएं। हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश में एक दीर्घकालिक और मजबूत साझेदारी बना सकते हैं। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को भारत की फुड बास्केट (अन्न का भंडार) बताते हुए कहा कि राज्य देश के कुल अनाज उत्पादन में लगभग 21 प्रतिशत का योगदान देता है।

### शिपरॉकेट की दमदार लिस्टिंग निवेशकों को 35% का फायदा

नईदिल्ली। ई-कॉमर्स कारोबार को तकनीकी और लॉजिस्टिक सेवाएं देने वाली कंपनी शिपरॉकेट के शेयरों ने बुधवार, 19 अगस्त को शेयर बाजार में दमदार शुरुआत की। कंपनी का शेयर एनएसई पर 131 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ। यह 97 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले 34 रुपये यानी 35.05 फीसदी का प्रीमियम है। बीएसई पर भी शिपरॉकेट की मजबूत लिस्टिंग हुई। यहां शेयर 129 रुपये पर लिस्ट हुआ, जो इश्यू प्राइस से 32 रुपये यानी करीब 33 फीसदी ज्यादा है। शिपरॉकेट के आईपीओ में एक लॉट में 154 शेयर रखे गए थे। ऊपरी प्राइस बैंड के आधार पर रिटेल निवेशकों को एक लॉट के लिए 14,938 रुपये लगाने थे। एनएसई पर 131 रुपये के लिस्टिंग भाव के हिसाब से निवेशकों को प्रति शेयर 34 रुपये का फायदा हुआ।

भूमिका रही है। केंद्रीय बैंक द्वारा नीतिगत दरों की स्थिर और संतुलित रखने से व्यापारिक गतिविधियों और निजी निवेश को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे और पूंजीगत विकास पर लगातार किए जा रहे बड़े खर्च ने आर्थिक पहिये को धमने नहीं दिया है। विशाल घरेलू उपभोक्ता आधार के कारण वैश्विक उतार-चढ़ाव का प्रभाव भारतीय बाजारों पर सीमित रहा है।

भारत आज दुनियाभर के निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आरबीआई की नई रियायती स्वैप सुविधा को वैश्विक स्तर पर व्यापक समर्थन मिला है। इस योजना ने महज दो महीने से भी कम समय में 2013 का 34 अरब डॉलर फंड जुटाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हाल ही में प्रकाशित ‘एसबीआई रिसर्च’ की रिपोर्ट के अनुसार, स्वैप योजना की समयावधि समाप्त होने तक कुल विदेशी फंड प्रवाह 80 से 85 अरब

डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। साथ ही, इस समय भारतीय शेयर बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की वापसी के स्पष्ट संकेत देखने को मिल रहे हैं। 31 जुलाई तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 692 अरब डॉलर से अधिक पहुंच गया, जो अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता को मजबूती देता है। इससे विदेशी संस्थागत निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, वैश्विक ऋण भूतान व प्रबंधन आसान होगा और घरेलू बाजार में महंगाई को नियंत्रित रखना संभव हो सकेगा। हालांकि, इन सबके बीच कई चुनौतियां भी दिखाई दे रही हैं। भारत के सामने वैश्विक अनिश्चितता, भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं और 55.6 प्रतिशत का कर्ज-जीडीपी अनुपात प्रमुख चुनौतियां हैं। युवाओं के लिए औपचारिक रोजगार व कौशल विकास बढ़ाना भी एक कठिन चुनौती है।





श्री नरेंद्र मोदी  
माननीय प्रधानमंत्री



## उद्योग और श्रम विभाग के आपसी समन्वय से संवर रहा छत्तीसगढ़



श्री विष्णु देव साय  
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जिस स्पष्ट नीति के साथ श्रमिकों और उद्योगों के समन्वित विकास को प्राथमिकता दी है, वह आज ठोस परिणामों के रूप में सामने आ रही है। श्रम विभाग की योजनाओं में यह भावना स्पष्ट झलकती है कि श्रमिक केवल आर्थिक इकाई नहीं, बल्कि समाज की आधारशिला हैं। उनके जीवन में स्थायित्व, सम्मान और सुरक्षा लाना ही सच्चे विकास का संकेत है।

2026 रजत जयंती वर्ष में छत्तीसगढ़ के विकास की वर्तमान यात्रा केवल योजनाओं और घोषणाओं की कहानी भर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे नेतृत्व की कथा है जिसने श्रमिक, युवा, उद्यमी और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। इस परिवर्तनकारी दौर में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व का विशेष रूप से उल्लेखनीय योगदान है। उनका कार्य केवल प्रशासनिक दक्षता तक सीमित नहीं है बल्कि सामाजिक संवेदनशीलता और दूरदर्शिता का जीवंत उदाहरण है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 25 वर्ष की अल्प आयु में उद्योग के क्षेत्र में जो एक नया इतिहास रचने का संकल्प लिया है वह किसी से छिपा नहीं है। उद्योग के क्षेत्र में आज छत्तीसगढ़ की अपनी एक अलग पहचान है। नई उद्योग नीति (2024-2030) में छत्तीसगढ़ के समावेशी विकास पर जोर दिया गया है।

### श्रमिकों के सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

- श्रमिकों के बच्चों को उत्कृष्ट विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा की सुविधा।
- मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों को लाखों रुपये की प्रोत्साहन राशि।
- पिछले दो वर्षों में सैकड़ों करोड़ रुपये सीधे श्रमिकों के खातों में हस्तांतरित।
- प्रति दिन हजारों श्रमिकों को योजनाओं का लाभ।
- आवास सहायता, दुर्घटना में त्वरित आर्थिक सहयोग।
- शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत मात्र 5 रुपये में गरम और पौष्टिक भोजन।

“यह पहले एक संवेदनशील और मानवीय शासन का परिचायक हैं, जो श्रमिकों के जीवन को अधिक सुरक्षित, सम्मानजनक और सशक्त बना रही हैं।”

### औद्योगिक विकास की नई ऊंचाईयां

- ⦿ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के माध्यम से निवेश और रोजगार के अवसरों में वृद्धि।
- ⦿ करोड़ों रुपये के निवेश प्रस्ताव, सैकड़ों नए उद्योगों की स्थापना और हजारों युवाओं को रोजगार।
- ⦿ नवा रायपुर में देश का पहला एआई डेटा सेंटर स्थापित करने की दिशा में कदम।
- ⦿ सेमीकंडक्टर, आईटी और स्टार्टअप जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन।
- ⦿ ई-निविदा प्रणाली और सिंगल विंडो सिस्टम से पारदर्शिता और निवेशकों का विश्वास मजबूत।
- ⦿ महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की सुविधा।
- ⦿ दूरस्थ क्षेत्रों में औद्योगिक विकास से सामाजिक समावेशन को बल।



### नेतृत्व में संवेदनशीलता और स्पष्ट दृष्टि

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अपने दूर दृष्टि सोच एवं विभागीय दाधित्यों के माध्यम से वह सिद्ध किया है कि यदि नेतृत्व में संवेदनशीलता और स्पष्ट दृष्टि हो, तो विकास केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाता है।

संवाद-48628/1



### रोजगार के व्यापक अवसर

1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये के अनुमानित प्रावधान वाला यह बजट राज्य की आर्थिक संरचना को सुदृढ़ करते हुए निवेश, औद्योगिक विस्तार और व्यापक रोजगार सृजन की स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत करता है। प्रदेश की लगभग 60% कार्यशील जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के विस्तार पर विशेष बल दिया गया है।



### रोजगार के व्यापक अवसर

औद्योगिक विकास नीति रोजगार केंद्रित विगत वर्ष लगभग 1,000 उद्योगों को उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किए गए, जिनके माध्यम से 8,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ तथा 15,000+ रोजगार के अवसर निर्मित हुए।



### सिंगल विंडो सिस्टम से प्रोत्साहनकारी वातावरण

Ease of Doing Business के अंतर्गत सिंगल विंडो सिस्टम एवं छत्तीसगढ़ जन विश्वास अधिनियम जैसे सुधारात्मक कदमों के माध्यम से शासन उद्योगों के लिए सुगम, पारदर्शी और प्रोत्साहनकारी वातावरण उपलब्ध करा रहा है।

**उद्योग विभाग का बजट**  
2024-25 : 648 करोड़ रुपये  
2026-27 : 1,750 करोड़ रुपये  
(उल्लेखनीय वृद्धि)



### उद्योगों के लिए अधोसंरचना विकास

- कचना (धमतरी) में प्रदेश की पहली चार मंजिला प्लग-एंड-जये फैक्ट्री।
- गाम तुता, नवा रायपुर अटल नगर में कन्वेक्शन सह एबनविशन सेंटर हेतु 25 करोड़ रुपये।
- भिलाई में व्यावसायिक परिसर हेतु 10 करोड़ रुपये।
- पटेवा (राजनांदगांव) में इलेक्ट्रॉनिक
- मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 हेतु 10 करोड़ रुपये।
- नवा रायपुर अटल नगर एवं राजनांदगांव में इंडस्ट्रियल फेसिलिटेशन कॉम्प्लेक्स हेतु 20 करोड़ रुपये।

- प्रदेश में 23 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु 250 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- नवीन औद्योगिक क्षेत्रों के लिए लैंड बैंक तैयार करने हेतु 200 करोड़ रुपये।
- उद्योगों को अनुदान एवं प्रतिपूर्ति के लिए 750 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- रायपुर, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद तथा जापान के ओसाका में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।



### विगत वर्ष लगभग

1,000 उद्योगों को उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किए गए, जिनके माध्यम से 8,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ तथा 15,000 + रोजगार के अवसर निर्मित हुए।

यह राज्य में निवेश अनुकूल वातावरण एवं औद्योगिक विश्वास का सशक्त संकेत है।

श्रम का सम्मान  
उद्योग का विकास  
छत्तीसगढ़ का विश्वास



शिक्षा  
सशक्तीकरण



सुरक्षा  
समृद्धि



निवेश  
रोजगार



समावेशी विकास  
खुशहाल छत्तीसगढ़

संकल्प हमारा  
विकास आपका  
भविष्य छत्तीसगढ़ का